जड़ी-बूटी बाजार

चुनौतियों, समाधानों और उपलब्धियों से भरे 7 सालों का सफर

विशेषांक

क्षेत्रीय एवं सुगमता केंद्र, राष्ट्रीय औषध पादप बोर्ड, आयुष मंत्रालय भारत सरकार, उत्तर भारत-1
आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान जोगिन्द्रनगर, मंडी, हिमाचल प्रदेश

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
आयुष मंत्रालय और
राज्य मंत्री
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत सरकार

आज़ादी का अमृत काल

सत्यमेव जयते

Minister of State
(Independent Charge) of
Ministry of Ayush and
Minister of State in
Ministry of Health and Family Welfare
Government of India

प्रतापराव जाधव
PRATAPRAO JADHAV

संदेश

मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विशेष रूप से आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने वर्ष 2014 में आयुष मंत्रालय की स्थापना करके भारतीय चिकित्सा पद्धतियों को एक नया सम्मान, दिशा और मार्गदर्शन दिया उनका यह दूरदर्शी निर्णय आज आयुष क्षेत्र को वैश्विक पहचान दिलाने में मील का महत्वपूर्ण पत्थर सिद्ध हो रहा है।

जैसाकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि अब मात्र सूचना क्रांति का ही युग नहीं रहा, बल्कि आयुष का युग है। यह प्रेरक कथन न केवल एक विचार है, बल्कि यह आज के भारत की बदलती सोंच और उसकी अपनी जड़ों से जुड़ने की भावना को भी दर्शाता है।

आयुष मंत्रालय के राष्ट्रीय औषध पादप बोर्ड के क्षेत्रीय एवं सुगमता केंद्र उत्तर क्षेत्र-1 (आरसीएफसी) द्वारा किए गए कार्य, चाहे वह किसानों को प्रशिक्षण देना हो, स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन करना हो या फिर औषधीय पौधों की वैज्ञानिक खेती को प्रोत्साहित करना हो, सभी सराहनीय हैं और आयुष मंत्रालय की दूरदर्शिता को साकार करने में सहायक हैं। औषधीय पौधे, जड़ी-बूटी हमारी परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों में उपयोग होने वाली दवाओं का आधार स्त्रोत हैं। यह केंद्र किसानों को इनकी खेती के प्रति जागरूक करने और प्रशिक्षण देकर उनके उत्पादों की बाजार में सही कीमत दिलाने में संजीवनी का काम कर सकता है।

मैं कामना करता हूं कि **'जड़ी-बूटी बाज़ार'** पत्रिका का यह वार्षिक विशेषांक न केवल जानकारी का स्रोत बने, बल्कि देशभर में आयुष से जुड़े नवाचारों और प्रयासों को एक नई दिशा देने वाला प्रेरणास्रोत सिद्ध हो।

मैं 'जड़ी-बूटी बाज़ार'पत्रिका के विशेषांक के सफल प्रकाशन पर संपादकीय टीम, लेखकों, शोधकर्ताओं और सभी सहयोगियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं।

(प्रतापराव जाधव)

नई दिल्ली

Room No. : 101, Ayush Bhawan, 'B' Block, GPO Complex, INA, New Delhi-110023
Tel : 011-24651955, 011-24651935 E-mail : minister-ayush@nic.in
Room No. 250-A, Nirman Bhawan, Maulana Azad Road, New Delhi-110011, Tel. : 011-23061551, 23061016
Residence : 23, Ashoka Road, New Delhi-110001, Tel.: 011-23740412, 23345478, Fax : 011-23740413

■ **श्री रोहित जम्वाल**
निदेशक, आयुर्वेद

■ **डॉ. अरुण चंदन**
क्षेत्रिय निदेशक एवं प्रधान अन्वेषक

तकनीकी टीम
- श्री शीतल चंदेल
- डॉ. स्वेता ठाकुर
- डॉ. मीनाक्षी ठाकुर

विपणन टीम
- श्री निखिल ठाकुर (विपणन प्रबंधक)
- सुश्री अविका सुब्बा (सलाहकार विपणन)

सहयोगी टीम
- श्री अभिषेक ठाकुर (ग्राफिक डिजाइनर)
- श्री विशाल ठाकुर (आशुलिपिक)
- श्री ऋषि कान्त (डेटा एंट्री ऑपरेटेर)
- श्रीमती अंजली (लेखाकार)
- श्रीमती ममता देवी (एम.टी.एस.)

सम्पर्क : आर.सी.एफ.सी. एन.आर.-1, जोगिंद्रनगर, मण्डी, हि.प्र., एनएमपीबी, आयुष मंत्रालय, मोबाईल नं.- 9015170106
ई मेल - rcfcnorthone@gmail.com | वेबसाइट - www | rcfcnorth.in

क्वालिटी प्लांटिंग मैटीरियल

औषधीय पौधों की गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री–एक आवश्यक नीतिगत पहल

आरसीएफसी नेटवर्क/दिल्ली

डॉ. अरुण चंदन

क्षेत्रीय निदेशक, आरसीएफसी नार्थ, जोगिन्द्रनगर

भारत प्राचीन काल से औषधीय पौधों और आयुर्वेदिक चिकित्सा का गढ़ रहा है। कोरोना महामारी के बाद दुनिया भर में जब आयुष पद्धति, हर्बल आहार और प्राकृतिक चिकित्सा की ओर झुकाव बढ़ा, तो भारत के पास अपने पारंपरिक ज्ञान को वैश्विक नेतृत्व देने का अद्वितीय अवसर आया। किंतु इस दिशा में प्रगति को स्थायी और भरोसेमंद बनाने के लिए औषधीय पौधों की गुणवत्तायुक्त रोपण सामग्री (Quality Planting Material) के लिए एक सशक्त कानूनी ढांचे की आवश्यकता महसूस की जा रही है। गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कानून की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

औषधीय पौधों की खेती में प्रयुक्त रोपण सामग्री की गुणवता को लेकर आज भी कोई ठोस विधिक प्रावधान नहीं है। इससे न केवल किसानों की आर्थिक सुरक्षा प्रभावित होती है, बल्कि आयुर्वेदिक उद्योग को भी गुणवत्तायुक्त कच्चे माल की आपूर्ति में कठिनाई आती है। इसीलिए अब यह आवश्यक हो गया है कि एक पारदर्शी, प्रमाणन आधारित और अनिवार्य कानून बनाया जाए, जिससे रोपण सामग्री की गुणवत्ता नियंत्रित की जा सके।

■ नर्सरी पंजीकरण और प्रमाणीकरण की प्रणाली का अभाव

वर्तमान में औषधीय पौधों की नर्सरियों का कोई एकीकृत पंजीकरण तंत्र या प्रमाणीकरण व्यवस्था नहीं है। इस स्थिति में कोई भी विक्रेता बिना गुणवत्ता प्रमाणपत्र के पौधे बेच सकता है, जिससे किसानों को भ्रमित करने और धोखा देने की संभावनाएं बनी रहती हैं। एक 'नर्सरी रजिस्ट्रेशन एवं प्रमाणीकरण अधिनियम' इस दिशा में एक ठोस सुधार हो सकता है।

■ देश में विकसित की गई उन्नत किस्मों की रोपण सामग्री की आवश्यकता

भारत के कृषि, वानिकी, उद्यानिकी एवं बागवानी विश्वविद्यालयों और CSIR के अधीन अनुसंधान संस्थानों ने वर्षों की मेहनत से सैकड़ों उन्नत औषधीय पौधों की किस्में (cultivars/varieties) विकसित की हैं। इनमें बेहतर उत्पादन क्षमता, औषधीय सक्रियता और क्षेत्रीय अनुकूलन की विशेषताएं होती हैं, लेकिन चिंता की बात यह है कि इन उन्नत किस्मों की गुणवतापूर्ण रोपण सामग्री किसानों तक सुगमता से नहीं पहुंच रही है। इनके गुणोत्तर विस्तार (multiplication) और प्रमाणिक वितरण प्रणाली की सख्त आवश्यकता है।

■ स्थानीय अनुकूलता और उद्योग साझेदारी की दिशा में आवश्यक सुधार

इन उन्नत किस्मों को व्यापक रूप से अपनाने से पहले देश के विभिन्न एग्रो-क्लाइमेटिक जोन में 'मल्टी लोकेशन ट्रायल्स' (MLTs) आवश्यक हैं, ताकि उनकी स्थानीय उपयोगिता प्रमाणित की जा सके। इससे विशिष्ट क्षेत्रों के लिए फसल सिफारिशें और प्रोडक्शन कॉरिडोर विकसित करने का मार्ग खुलेगा।

साथ ही, औषधीय उद्योग को किसान समूहों के साथ साझेदारी करते हुए तकनीकी और विपणन सहयोग देना चाहिए। इससे न केवल कच्चे माल की गुणवत्ता सुनिश्चित होगी, बल्कि किसानों को उनकी मेहनत का मूल्य भी मिलेगा।

यह भी सत्य है कि कुछ वर्गों द्वारा संवर्धित किस्मों पर सवाल उठाए जाते हैं और पारंपरिक किस्मों को प्राथमिकता दी जाती है, परंतु जब बाजार में उन्हीं पारंपरिक किस्मों का कोई प्रीमियम मूल्य नहीं है, तो किसान की मेहनत की भरपाई कैसे होगी? ऐसे में प्रमाणन और मूल्य निर्धारण दोनों ही जरूरी हो जाते हैं।

■ पंजाब और हरियाणा में जल संकट के बीच औषधीय खेती का संभावित समाधान

पंजाब और हरियाणा जैसे राज्य वर्षों से चावल और गेहूं जैसी जल-गहन फसलों पर निर्भर हैं, जिससे इन राज्यों में जलस्तर तेजी से गिरा है। राज्य सरकारें अब फसल विविधिकरण की दिशा में कदम बढ़ा रही हैं। औषधीय पौधों की खेती न केवल कम जल की आवश्यकता के कारण लाभकारी है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय मांग को देखते हुए उच्च आय का माध्यम भी बन सकती है।

यह अत्यंत उपयुक्त समय है कि इन राज्यों में औषधीय खेती की पायलट परियोजनाएं चलाई जाएं, जिससे नीति-निर्माताओं को भविष्य के लिए एक प्रतिस्पर्धी और पर्यावरण-संवेदनशील मॉडल तैयार करने में मदद मिले।

■ कच्चे माल की कीमतों में अंतर - किसानों की सबसे बड़ी पीड़ा

औषधीय खेती में एक गंभीर समस्या यह भी है कि किसानों को उनके उत्पाद का सही मूल्य नहीं मिल पाता, जबकि वही कच्चा माल बाजार में कई गुना दाम पर बिकता है। व्यापारियों और उद्योगों द्वारा दी जाने वाली कीमत और किसान की लागत और अपेक्षा में बड़ा अंतर बना रहता है।

अब आवश्यकता है कि नीति स्तर पर औषधीय पौधों के लिए न्यूनतम आश्वस्त मूल्य (Assured Price) अथवा अनुबंध आधारित मूल्य गारंटी मॉडल तैयार किया जाए। इससे किसानों को विश्वास मिलेगा, उनकी आय स्थिर होगी और औषधीय खेती में युवाओं की भागीदारी भी बढ़ेगी।

यदि भारत को वैश्विक औषधीय बाजार में अग्रणी बनाना है, तो यह अनिवार्य है कि हम औषधीय पौधों की रोपण सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कानूनी ढांचा, प्रमाणन प्रणाली, स्थानीय परीक्षण और उद्योग-किसान सहयोग जैसी बहु-आयामी रणनीति अपनाएं। साथ ही, किसानों के उचित मूल्य और जल संरक्षण जैसे पहलुओं को जोड़कर औषधीय खेती को एक सशक्त, समावेशी और टिकाऊ कृषि विकल्प के रूप में प्रस्तुत करें।

जड़ी-बूटियों की खेती-व्यापार के लिए वन स्टॉप सेल्यूशन

हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगढ़ और दिल्ली को औषधीय कृषिकरण सिखा रहा औषध पादप बोर्ड का क्षेत्रीय सुगमता केंद्र

औषधीय पौधों की खेती के संरक्षण, विकास और विपणन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा संस्थान, कई किसानों को औषधीय खेती की ओर मोड़ा

आरसीएफसी नेटवर्क/हिमाचल प्रदेश

पौधों के क्षेत्र से संबंधित मामलों को समन्वित करने, इस संबंध में योजनाओं को तैयार और कार्यान्वित करने के लिए नवंबर 2000 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड की स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय औषध पादप बोर्ड राष्ट्रीय आयुष मिशन के औषधीय पौधों के संरक्षण विकास और सतत प्रबंधन के लिए सेंटर सेक्टर योजना और औषधीय पौधों की विकास योजनाओं का कार्यान्वयन कर रहा है।

औषधीय पौधों के क्षेत्र में गतिविधियों में समन्वय स्थापित करने और छह विभिन्न क्षेत्रों (पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, मध्य और उत्तर पूर्व) में क्षेत्रीय सुगमता केंद्र स्थापित किए गए। आयुर्वेद विभाग हिमाचल प्रदेश के जोगिंद्रनगर स्थित आयुर्वेद रिसर्च इंस्टीट्यूट को औषधीय पौधे के क्षेत्र से संबंधित कार्य के अनुभव और योग्यता के आधार पर उत्तर भारतीय राज्यों के लिए क्षेत्रीय एवं सुगमता केंद्र के लिए चुना गया।

आरसीएफसी जोगिंद्रनगर के तहत हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगढ़ और दिल्ली जैसे राज्य व केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। यह क्षेत्रीय सुगमता केंद्र उत्तर भारत में औषधीय पौधों के उत्पादकों, किसानों, शोधकर्ताओं, व्यापारियों और अन्य हितधारकों के लिए एक स्टॉप शॉप के रूप में राज्य औषध पादप बोर्ड के साथ निकट समन्वय में कार्य कर रहा है। यह क्षेत्रीय सुगमता केंद्र सुविधाओं, औषधीय पौधों की खेती के संरक्षण, विकास, विपणन, सहयोगियों व औषधीय पौधों के उत्पादकों के लिए एक सेवा खिड़की प्रदान कर रहा है और प्रौद्योगिकी प्रसार के संदर्भ में हितधारकों का समर्थन कर रहा है।

डॉक्टर अरुण चंदन
क्षेत्रीय निदेशक
आरसीएफसी, जोगिंद्रनगर

आरसीएफसी जोगिंद्रनगर की गतिविधियां

- जड़ी-बूटियों के विक्रेताओं-क्रेताओं के बीच करार करवाना।
- उत्पादकों को गुणवतापरक प्लांटिंग मैटीरियल की सुविधा देना।
- तकनीक के प्रयोग से जड़ी-बूटियों के कारोबार में मूल्यवर्धन करना।
- गुणवतापरक प्लांटिंग मैटीरियल के लिए टिशू कल्चर लैब उपलब्ध करवाना।
- जड़ी-बूटियों के रखरखाव के लिए स्टोर हाउस की व्यवस्था करना।
- जड़ी-बूटियों के विपणन के लिए आउटलेट स्थापित करना।
- जड़ी-बूटियों की खेती को बढ़ावा और वैज्ञानिक दोहन को बल देना।
- जड़ी-बूटियों की खेती से रोजगार सृजन और ग्रामीण आर्थिकी को मजबूत करना।

आरसीएफसी जोगिंद्रनगर की उपलब्धियां

- यह क्षेत्रीय केंद्र औषधीय पौधों से संबंधित सभी मामलों-समाधानों के लिए एक स्टॉप शॉप के रूप में कार्य कर रहा है और इस क्षेत्र से संबंधित अनुसंधान गतिविधियों का आयोजन कर रहा है।
- स्थानीय स्टेक होल्डर्स, प्रतिष्ठानों और संगठनों के साथ मिलकर प्राथमिक संसाधन, ग्रेडिंग, मार्केटिंग सुविधा प्रदान करने में मदद कर रहा है।
- उत्पादकों, कलेक्टरों सहित संबंधित हितधारकों के बीच प्रबंधकीय और तकनीकी कौशल विकसित कर रहा है। यह केंद्र प्रशिक्षण, कार्यशालाओं, सेमिनार आदि के आयोजनों से अपने हितग्राहियों की मदद कर रहा है।
- विशेष रूप से लुप्तप्राय और उच्च मांग वाली प्रजातियों, जैविक खेती और पहले से विकसित कृषि तकनीकों के अनुकूल फील्ड परीक्षणों के साथ औषधीय पौधों की कृषि प्रौद्योगिकी का विकास कर रहा है।
- औषधीय पौधों के संरक्षण, अनुकूल खेती, प्रौद्योगिकी उन्नयन, प्रशिक्षण और अनुसंधान पर जानकारी प्रदान करने के साथ उन गतिविधियों से संबंधित विभागों को शामिल करने के लिए प्रयास कर रहा है।
- यह सुविधा केंद्र क्षेत्र विशिष्ट गुणवत्ता वाली रोपण सामग्री का विकास कर रहा है और इसके साथ संबंधित मुद्दों को वैज्ञानिक रूप से प्रचारित कर रहा है।
- संबंधित राज्यों में अच्छी कृषि पद्धतियां (जीएपी), गुड फील्ड कलेक्शन प्रैक्टिस (जीएफसीपी) इत्यादि पर पहलों को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है।
- यह सुविधा केंद्र राज्यों में औषधीय पौधों के विभिन्न हितधारकों को एक साथ लाने के लिए प्रयास कर रहा है और परियोजना प्रस्ताव तैयार करने के लिए क्षेत्र में विभिन्न संगठनों की सहायता कर रहा है।
- यह केंद्र हितधारकों के साथ समय-समय पर बैठकों, कार्यशालाओं, परामर्शों का आयोजन कर रहा है। औषधीय पौधों, उपज आदि की बिक्री की सुविधा, मांग व आपूर्ति मुद्दों को हल करने का प्रयास कर रहा है।
- यह केंद्र विपणन सुविधा के विकास के साथ मांग, मात्रा बेचने और प्रमुख प्रजातियों की कीमत पर डेटाबेस विकसित करने में प्रयत्नशील है।
- संबंधित राज्यों में विभिन्न संगठनों को एनएमपीबी द्वारा मंजूर की गई परियोजनाओं की समीक्षा, मूल्यांकन और उनका संचालन कर रहा है।
- यह सुविधा केंद्र संबन्धित राज्यों में औषधीय पौधों के सभी संबंधित क्षेत्रों के डाटाबेस को इकट्ठा करने के साथ संबंधित क्षेत्र के विभिन्न राज्यों के डेटाबेस का एकीकरण कर रहा है।
- यह सुविधा केंद्र औषधीय पौधों के क्षेत्र में नए शोध निष्कर्षों और नई प्रौद्योगिकियों का प्रसार कर रहा है। यह केंद्र सूचना, शिक्षा और संचार के लिए रणनीति बनाकर गतिविधियों को लागू कर रहा है।
- यह सुविधा केंद्र एनएमपीबी द्वारा समर्थित गतिविधियों की सफलता की कहानियों के दस्तावेज तैयार करवा कर उन्हें प्रसारित कर रहा है। यह क्षेत्रीय एवं सुगमता केंद्र अपनी विभिन्न गतिविधियों व उपलब्धियों की वार्षिक रिपोर्ट तैयार कर प्रकाशित कर रहा है।

‘गोरे बाबे के फार्म’ से जड़ी-बूटियों की खेती की शुरुआत, ‘सोहावी’ की कांगड़ गांव को सौगात

■ बना देश का पहला मैनमेड मेडिसिनल फॉरेस्ट ■ पैदा हुआ दुनिया का दूसरी सबसे उत्तम किस्म का शहद

आरसीएफसी नेटवर्क/पंजाब

यह कहानी है पंजाब के रोपड़ जिले के नूरपुर बेदी के पास स्थित कांगड़ गांव की सोहावी फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी की, जो औषधीय कृषिकरण को लेकर पंजाब में उत्कृष्टता का केंद्र बन गई है। इस प्रेरक कहानी में ‘गोरा बाबा’ एक बड़ा किरदार है, जिसके माध्यम से राष्ट्रीय औषध पादप बोर्ड के क्षेत्रीय सुविधा केंद्र की टीम जड़ी-बूटियों और औषधीय पौधों के जैविक प्रमाणीकरण के लिए इस गांव तक पहुंची। इस कहानी के दूसरे किरदार नरेश कुमार के चलते इस गांव में सोहावी फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी की पहल हुई।

इस कहानी के तीसरे किरदार प्रेमजीत चोपड़ा के प्रवेश के साथ ही गांव में मैनमेड मेडिसनल फॉरेस्ट बनाने का आइडिया आया, जिसके लिए क्षेत्रीय सुविधा केंद्र ने क्वालिटी प्लांटिंग मैटीरियल उपलब्ध करवाकर मदद की। मेडिसनल फॉरेस्ट से कड़ी पत्ते की कहानी का शुरू हुई और आईआईटी रोपड़ की एंट्री हुई। फिर इस मेडिसनल फॉरेस्ट में शहद उत्पादन शुरू हुआ और यहां के कड़ी पत्ते से तैयार शहद ने लंदन में आयोजित एक शहद प्रतियोगिता में दुनिया के दूसरे सबसे उत्तम शहद होने का अवार्ड जीता।

ऐसे पड़ी सोहावी फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी की नींव

साल 2018 में राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड के क्षेत्रीय सुविधा केंद्र की टीम औषधीय पौधों के जैविक प्रमाणीकरण के लिए ‘गोरा बाबा’ के नाम से मशहूर फ्रांस में जन्मे ब्रिटिश नागरिक दर्शन सिंह रुडेल से मिलने कांगड़ गांव में स्थित उनके फार्म पर पहुंची थी। दर्शन सिंह भारत में घर बनाकर और सिख धर्म अपना पिछले 20 वर्षों से इस गांव में जैविक फार्म चला रहे हैं। यह फार्म पंजाब में जैविक और औषधीय खेती में उत्कृष्टता का केंद्र है।

गोरे बाबे के फार्म में राष्ट्रीय औषध पादप बोर्ड के क्षेत्रीय सुविधा केंद्र की टीम से नरेश कुमार की मुलाकात सोहावी फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी की नींव का आधार बन गई। नरेश कुमार की अगुवाई में गांव के नौ युवाओं ने बिना किसी सरकारी मदद से साल 2019 में सोहावी फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी का गठन किया।

कांगड़ गांव का कांगड़ा कनेक्शन

सोहावी पिछले चार पांच सालों में लेमन ग्रास, मोरिंगा और सर्पगंधा जैसे कई औषधीय पौधों की खेती कर रही है। सोहावी उन्नत किस्मों के मेडिसिनल प्लांट्स और मिलेट्स का क्वालिटी प्लांटिंग मैटीरियल जुटाकर उसको अपनी नर्सरी में मल्टीप्लाई कर खेती करती है। पंजाब एग्रो ने सोहावी से साथ जुड़े छब्बीस किसानों को ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट प्रदान किया है।

सोहावी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला के किसानों से एलोवेरा खरीदती है। कांगड़ा के एलोवेरा के क्वालिटी प्लांटिंग मैटीरियल से कांगड़ गांव में एलोवेरा की खेती की जा रही है। इस साल हजारों पौधे लगा कर एलोवेरा के कृषिकरण का दायरा और बढ़ाया जा रहा है। सोहावी ने एलोवेरा का प्रोसेस्ड मैटीरियल बेचने के लिए हिमाचल प्रदेश के फार्मा हब बद्दी की एक कंपनी के साथ करार किया है।

क्षेत्रीय सुविधा केंद्र ने सोहावी फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी को कांगड़ा से हल्दी का क्वालिटी प्लांटिंग मैटीरियल उपलब्ध करवाया। सोहावी ने हल्दी का और भी अच्छी क्वालिटी का प्लांटिंग मैटीरियल ढूंढ कर बड़ी मात्रा में हल्दी की खेती शुरू की।

आधुनिक टेक्नोलॉजी वाली प्रोसेसिंग यूनिट

पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने सोहावी फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी को पाइप्स आधारित आधुनिक टेक्नोलॉजी वाली पंजाब की सर्वश्रेष्ठ यूनिट्स में से एक ड्राइंग यूनिट स्थापित करने में सहयोग किया है। इसमें आंवला और हल्दी सुखाई जाती है। नेशनल अरोमा मिशन के तहत यहां डिस्ट्रीब्यूटर यूनिट भी लगाया है।

सोहावी ने एफएसएसएआई लाइसेंस प्राप्त कर गन्ने को प्रोसेस कर गुड़ बनाने का प्रोसेसिंग यूनिट भी स्थापित किया है। क्षेत्रीय सुविधा केंद्र ने सोहावी को इन्क्यूबेशन के लिए आईआईटी रोपड़ के साथ जोड़ने में मदद की, जिसके बाद आईआईटी रोपड़ सोहावी को टेक्निकल स्पोर्ट दे रही है।

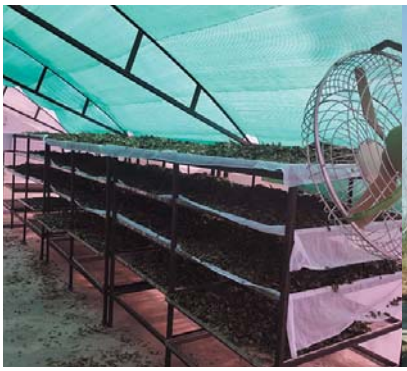

सोहावी ने लॉन्च किए अपने ब्रांड

सोहावी ने प्रोसेसिंग कर हल्दी का अपना ब्रांड लॉन्च किया है। कंपनी शोध के बाद अब सरसों में कड़ी पत्ते को मिक्स कर तेल की नई वैरायटी लॉन्च करने जा रही है। सोहावी ने अपनी आरएंडडी से खुद डिस्टिल कर हल्दी के पत्तों का तेल निकाला है और उस तेल की मार्केट एक्सप्लोर की है। इस तेल को नारियल तेल के साथ मिला कर कोल्ड क्रीम बनाई है। सोहावी फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी गन्ने की प्रोसेसिंग कर गुड़ बनाती है। सोहावी आंबले की कैंडी बनाकर बीटूबी में बड़े-बड़े ढाबों और रेस्टोरेंट्स को सप्लाई कर रही है।

मैनमेड मेडिसनल फॉरेस्ट बनाने का आइडिया

हजार एकड़ में फैली हुई चोपड़ा परिवार की प्रॉपर्टी 'कीकर लॉज' के लिए कांगड़ गांव मशहूर है। इस समय यह प्रॉपर्टी कॉर्पोरेट के लिए हॉलिडे डेस्टिनेशन है। कॉर्पोरेट के लोग यहां एडवेंचर एक्टिविटीज करने के लिए आते हैं। इस परिवार के दूसरे भाई प्रेमजीत चोपड़ा इंग्लैंड में सेटल हैं। उनके हिस्से गांव का पैतृक जंगल आया है। वह अपने जंगल में कुछ करने की योजना पर काम कर रहे थे।

गांव में जब क्षेत्रीय सुविधा केंद्र के सहयोग से सोहावी ने औषधीय कृषिकरण की पहल की, उस दौरान प्रेमजीत चोपड़ा की मुलाकात क्षेत्रीय सुविधा केंद्र की टीम से हुई, जिसने उन्हें इंडिया का पहला मैनमेड मेडिसनल फॉरेस्ट बनाने का आइडिया दिया। इस पर सहमति बनने के बाद कंडी खोज केंद्र से उनके जंगल का सर्वे करवाया गया, जिससे जंगल में पैदा होने वाले सभी मेडिसिनल प्लांट्स की लिस्ट बन गई।

शहद के लिए कड़ी पत्ते का प्रयोग

जंगल में सस्टेनेबल हार्वेस्टिंग का बिजनेस प्लान बनाया गया। पूरे जंगल को ब्लॉकों में बांट कर जंगल के बीच बहने वाले नाले में कैचमेंट सिस्टम बना दिया गया। नाले में उगे कड़ी पत्ता पर काम शुरू हुआ और उसके कई बड़े ऑर्डर मिले। जब यह अध्ययन किया गया कि प्रेमजीत चोपड़ा के फॉरेस्ट में कौन-कौन से फ्लावर का सीजन है, जो शहद उत्पादन के लिए सूटेबल हो सकता है, तो पता चला कि पंद्रह अप्रैल से लेकर मई की पंद्रह तारीख तक यहां कड़ी पत्ते की फ्लावरिंग होती है। इसी समय किकर फैमिली के फ्लाई नाम के प्लांट की भी फ्लावरिंग होती है।

क्षेत्रीय सुविधा केंद्र के सहयोग से सहारनपुर की बायो ऊर्जा फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी के संस्थापक एवं शहद के बड़े एक्सपर्ट संजय सैनी ने अपना मौनवंश प्रेमजीत चोपड़ा के फॉरेस्ट में माइग्रेट कर दिया। शहद उत्पादन के लिए चीन से हनीकॉम मंगवाए गए। जंगल में ऐसे दस हजार हनीकॉम लगाए गए और 10 हजार लीटर हनी उत्पादन का टारगेट रखा गया।

हयात होटल के ब्रेकफास्ट में कांगड़ का शहद

दुर्भाग्य से भारी बरसात के चलते शहद उत्पादन में बड़ा नुकसान हो गया, फिर भी अच्छी मात्रा में शहद हार्वेस्ट हो गया। अब इस शहद की टेस्टिंग की बारी थी। भारत में कई जगह इस शहद की टेस्टिंग कारवाई, लेकिन कोई भी संस्थान इसकी टेस्ट रिपोर्ट नहीं दे पाया। तब इस शहद को टेस्टिंग के लिए जर्मनी की इंटेक लैब में भेजा गया। इस लैब ने अपनी रिपोर्ट में कहा गया कि लैब की हिस्ट्री में इससे पहले इतने बढ़िया गुणवत्ता वाले शहद का टेस्ट नहीं किया। लैब ने सारे स्टैंडर्ड सहित इस शहद की रिपोर्ट बनाकर उन्हें भेज दी।

इसके बाद लंदन में आयोजित ग्लोबल हनी फेस्टिवल में इस शहद को प्रदर्शित किया गया, जहां इस शहद को दुनिया के सेकंड बेस्ट शहद का प्राइज मिला। फेस्टिवल के दौरान ही इस शहद की खरीद के लिए एग्रीमेंट हो गया। मेहमाननवाजी उद्योग के इंटरनेशनल ब्रांड हयात ग्रुप ने अपने कस्टमर्स के ब्रेकफास्ट की छोटी शीशियों के लिए इस शहद को शामिल कर लिया।

मैनमेड मेडिसनल फॉरेस्ट के ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन की कवायद

क्षेत्रीय सुविधा केंद्र की टीम ने कांगड़ गांव के जंगल के इस इस शहद को आध्यात्मिक गुरु श्रीश्री रवि शंकर को भेंट किया, जिसे उन्होंने खूब सराहा। सोशल मीडिया पर इस पोस्ट के वायरल होने के बाद देशभर में इस शहद की मांग बढ़ गई और इस शहद को 2000 रुपए प्रति लीटर की कीमत मिली।

क्योंकि ये सेक्शन फोर का फॉरेस्ट है, जिसके चलते इसमें कंस्ट्रक्शन नहीं की जा सकती। इसमें सिर्फ पर्यावरण प्रेमी गतिविधियां हो सकती हैं। ऐसे में प्रेमजीत चोपड़ा ने तीन कंटेनरों में अपना ऑफिस, कलेक्शन सेंटर और ड्राइंग स्टोर बना कर जंगल के पास स्थापित किए हैं।

विश्व मधुमक्खी दिवस पर एक फंक्शन में कांगड़ के हनी की लॉन्चिंग की गई। यहां मधुमक्खी म्यूजियम भी बनाया है। पंजाब में ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन में अहम रोल अदा कर रही पंजाब एग्रो से कांगड़ के इस जंगल को ऑर्गेनिक सर्टिफाई करवाने के लिए प्रयास चल रहा है।

आयुष सर्टिफाइड शहद, मेडिसनल आयुष फॉरेस्ट

क्षेत्रीय सुविधा केंद्र के क्षेत्रीय निदेशक डॉ. अरुण चंदन कहते हैं कि कड़ी पत्ता औषधीय पौधा है और शहद आयुर्वेद का इंग्रेडिएंट है। वे कहते हैं कि इस शहद की बड़ी डिमांड का मतलब यह है कि यह शहद आयुष सर्टिफाइड शहद की दिशा में एक बड़ी कामयाबी है। वे कहते हैं कि भविष्य में यह जंगल देश का पहला मेडिसनल आयुष फॉरेस्ट बनेगा, जो वन संरक्षण के साथ लोगों में जागरूकता भी लाएगा।

क्षेत्रीय सुविधा केंद्र के सहयोग से कांगड़ के इस मैनमेड मेडिसनल फॉरेस्ट में औषधीय पौधों की एक लाख सेंपलिंग लगाई जा चुकी हैं, जिनमें कई तरह के औषधीय गुणों वाले पेड़ व जड़ी- बूटियां शामिल हैं। यहां लुप्तप्राय हो चुकी कई प्रजातियों के पौधों और पेड़ों का संरक्षण भी शुरू हुआ है। अब इस मेडिसनल फॉरेस्ट में स्टूडेंट्स भी आने लगे हैं।

ऐसी मल्टीपर्पज प्रोसेसिंग मशीन बनाई जड़ी-बूटियों की खेती से बढ़ गई कमाई

आरसीएफसी नेटवर्क/हरियाणा

जड़ी-बूटियों की खेती करने वाले किसान धर्मवीर कंबोज का नाम बड़ी इज्जत से लेते हैं। उन्होंने एक मल्टीपरपज प्रोसेसिंग मशीन बनाई है, जो कई तरह के उत्पादों की प्रोसेसिंग कर सकती है। मशीन एक घंटे में दो क्विंटल एलोवेरा का जूस बनाने की क्षमता रखती है। इस मशीन से आंवला, अमरूद, स्ट्रॉबेरी जैसे फलों सहित गाजर, अदरक, लहसुन की भी प्रोसेसिंग की जा सकती है। इस मशीन से सब्जियों का छिलका उतारने, कटाई करने, उबालने और जूस बनाने का काम भी किया जाता है। इस मशीन का उन्होंने पेटेंट कराया है। यह मशीन सिंगल फेज बिजली से चलती है और इसमें मोटर की रफ्तार को नियंत्रित करने की व्यवस्था है। धर्मवीर कंबोज अब तक ऐसी सैंकड़ों मशीनें बेच चुके हैं। अफ्रीका और नेपाल ने भी उनसे ऐसी मशीनें खरीदी हैं। उन्होंने अधिकांश मशीनें स्वयं सहायता समूहों को बेची गई हैं।

धर्मवीर ने एक वेजीटेबल कटर मशीन भी बनाई है, जो एक घंटे में 250 किलो सब्जियों को काट सकती है। उन्होंने फलों, सब्जियों, इलायची और जड़ी-बूटियों को सुखाने वाली कम कीमत की एक मशीन भी बनाई है। वर्ष 2013 में फूड प्रोसेसिंग मशीन बनाने पर उन्हें नेशनल अवार्ड मिला है। हरियाणा के यमुनानगर जिले के दंगला गांव के धर्मवीर कंबोज जड़ी-बूटियों की खेती और उनकी प्रोसेसिंग से एक करोड़ रूपए तक सलाना कमा रहे हैं।

ट्रेक्टर से चलने वाला मोबाइल रेन टेंकर

धर्मवीर ने मोबाइल सिंचाई मशीन बनाई है। इस मशीन की तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने खूब सराहना की थी। मशीन को राष्ट्रपति भवन में प्रदर्शित किया गया था। इसको रेन टेंकर नाम दिया गया है। इसके सिंचाई सिस्टम में छह हजार लीटर पानी की क्षमता वाला टेंकर लगाया गया। इसे ट्रैक्टर की सहायता से खींच कर खेतों में ले जाकर फसलों की सिंचाई की जा सकती है। टेंकर के बिल्कुल पीछे चैस्सी पर एक पांच हार्स पॉवर का ईंजन लगाया गया है। इसकी सहायता से लगभग 150 फुट के दायरे में बरसात की जा सकती है।

सोलर बैटरी से चलने वाली झाड़ू मशीन

धर्मवीर ने सोलर बैटरी से चलने वाली झाड़ू मशीन तैयार की है। इस मशीन का निर्माण करने में घरेलू सामान का प्रयोग किया गया है। झाड़ू वाली यह मशीन सड़क पर पड़े पत्ते व अन्य कूड़ा- कर्कट उठाकर पानी के साथ सफाई करती है। इस मशीन को बहुत ही आसानी से चला सकते हैं।

धर्मवीर कहते हैं कि भविष्य में इस मशीन को गोबर उठाने के कार्य में भी प्रयोग किया जाएगा। ई रिक्शा वाली झाड़ू की मशीन से सात फुट चौड़ाई में साफ-सफाई का काम किया जा सकता है। यह मशीन रास्ते में पड़े कूड़े-कर्कट को निर्धारित स्थान पर डालती है। मशीन को बनाने पर एक लाख रुपए खर्च आया है।

कामयाबी के सफर में संघर्ष के दिन

धर्मवीर कंबोज कभी दो जून की रोटी के लिए दिल्ली की सड़कों पर ऑटो रिक्शा चलाते थे। एक सड़क हादसे का शिकार हुए तो मजबूरन गांव लौटना पड़ा। गांव के किसानों के भ्रमण में अजमेर जाने का अवसर मिला। वहां पर आंवले की मिठाइयां बना रहीं महिलाओं को देखकर ऐसा करने का बिजनेस आइडिया आया। व्यवसायिक स्तर पर गाजर अथवा आंवले को कद्दूकस करने के लिए जो औजार थे, उनसे न केवल ज्यादा समय की बर्बादी होती, बल्कि हाथ छिलने का डर भी बना रहता। इसी जरूरत ने उन्हें ऐसी मशीन बनाने की दिशा में काम करने को प्रेरित किया। उन्होंने इसके लिए कई प्रयोग किए और रात-दिन एक कर मशीन तैयार करने में सफलता हासिल की। उनकी मल्टीपर्पज मशीन ने प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में कमाल कर दिया।

काम को सम्मान

धर्मवीर कंबोज को वर्ष 2009 में कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने सम्मानित किया। वर्ष 2010 में तत्कालीन केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार ने उन्हें फार्मर साइंटिस्ट का अवार्ड दिया। वर्ष 2013 में फूड प्रोसेसिंग मशीन बनाने पर उन्हें नेशनल अवार्ड मिला।

मल्टीपर्पज मशीन बनाने पर वर्ष 2015 में जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति रॉबर्ट मुगांबे ने उनको सम्मानित किया। देश की कई संस्थाएं उन्हें सम्मानित कर चुकी हैं। वे अब कृषि टीचर के रोल में भूमिका अदा कर रहे हैं। वे सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को घरेलू स्तर पर फूड प्रोसेसिंग के लिए निशुल्क प्रशिक्षण देते हैं।

जड़ी-बूटियों की खेती से कमाल

दिल्ली छोड़कर जब गांव लौटे तो धर्मवीर ने औषधीय पौधों की खेती शुरू कर दी। अकरकरा, अश्वगंधा, सफेद मूसली, ब्रह्मी, बच, एलोवेरा, कालमेघ, गिलोए, तुलसी व आंवला की खेती करने के साथ ही उन्होंने प्रोसेसिंग मशीनें बनाने के प्रयास शुरू किए। धर्मवीर अपनी फसल को प्रोसेसिंग कर तुलसी का तेल, सोयाबीन का दूध, हल्दी का अर्क, गुलाब जल, जीरे का तेल, पपीते और जामुन का जैम, अमरूद जूस, आइसक्रीम और टॉफी बनाते हैं। उनके कारोबार से 35 महिलाएं जुड़ी हैं। धर्मवीर कहते हैं कि उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन उनकी बनाई मशीनें कृषि आर्थिकी का चेहरा बदलने में कारगर सिद्ध होंगी। औषध पादप बोर्ड का क्षेत्रीय सुगमता केंद्र कृषक टीचर के तौर पर उनकी सेवाएं उत्तर भारत के जड़ी-बूटियों की खेती करने वाले किसानों को प्रोसेसिंग में प्रशिक्षित करने के लिए ले रहा है।

25 साल पहले मार्केटिंग की चुनौती ने किसान को बनाया शोधकर्ता - अब खेत से लोक आयुर्वेद की क्रांति

आरसीएफसी नेटवर्क/उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के छोटे से गांव अमोरा में रहने वाले 77 वर्षीय रंग बहादुर आज केवल किसान नहीं, बल्कि एक ऐसे 'आयुर्वेदिक शोधकर्ता' हैं, जिनका कार्य लोक स्वास्थ्य, पारंपरिक ज्ञान और ग्रामीण नवाचार का अद्भुत संगम है।

जब अधिकांश लोग खेती में मूल्य न मिलने से निराश हो जाते हैं, रंग बहादुर ने पारंपरिक फार्मूलों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से परखा, आजमाया और सिद्ध किया।

उन्होंने निराश न होकर फसल के न बिकने को ही अपनी ताकत बना लिया और 'वैल्यू एडिशन' करके कार्य की नई शुरुआत की।

उनके कार्यों को सम्मान देते हुए सरकार ने उन्हें 'औषध पंडित' की उपाधि दी है और लोग उन्हें सम्मान से 'गांव के आयुर्वेदाचार्य' कहने लगे हैं।

लोक ज्ञान और शोध का संगम-दीर्घायु का फार्मूला

रंग बहादुर ने अपनी ग्रामीण शोधशाला में मुलहठी, शहद और शतावरी का एक विशेष संयोजन तैयार किया है, जिसके बारे में संदर्भ अग्निपुराण में है कि यदि इसका सेवन बताई गई विधि से तीन महीने किया जाए, तो दीर्घायु संभव है।

मुलहठी आयुर्वेदिक औषधियों में बहुतायत उपयोग में आती है, वहीं शतावरी भारतीय सांस्कृतिक परंपरा में जीवनवर्धक मानी जाती है। वे स्वयं इसे उगाते भी हैं। रंग बहादुर ने इस लोक विश्वास को वैज्ञानिक शोध के साथ जोड़ते हुए एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया है।

केले से बनता प्राकृतिक कपूर पारंपरिक स्रोत की पुनराविष्कार

रंग बहादुर ने पाया कि भारत में उपलब्ध अधिकांश कपूर सिंथेटिक होता है, जबकि आयुर्वेदिक रूप से इसका प्राकृतिक स्रोत आवश्यक है।

उन्होंने प्राचीन ग्रंथों से प्रेरणा लेकर केले के तने से प्राकृतिक कपूर तैयार करने की विधि खोज निकाली। इस प्रक्रिया को और गहराई से समझने के लिए वे म्यांमार और चेन्नई के पारंपरिक समुदायों से भी संपर्क कर रहे हैं।

यह खोज आयुर्वेदिक सुगंध, ऑक्सीजन स्पोर्ट और रेस्पिरेटरी सप्लीमेंट के क्षेत्र में एक नई दिशा खोल सकती है।

फसल नहीं, दर्द बेचा-जब किसान बना वैद्य

2000 के दशक की शुरुआत में रंग बहादुर ने सफेद मूसली और स्टीविया की खेती की, परंतु उत्पाद बेचने में असफलता मिली। यह संकट उनके जीवन का मोड़ बना। उन्होंने जड़ी-बूटियों के गुण, लोककथाएं और पौराणिक चिकित्सा ग्रंथों का गहन अध्ययन शुरू किया।

उन्हें आयुर्वेदिक ग्रंथों को पढ़ने का जबरदस्त शौक है। वे न केवल चरक संहिता, भावप्रकाश और शारंगधर संहिता जैसे ग्रंथों को नियमित पढ़ते हैं, बल्कि उनमें उपयोगी श्लोक और पृष्ठ संख्या तक उन्हें कंठस्थ हैं। वे अक्सर कहते हैं, 'अगर शरीर रोगी है, तो समाधान ग्रंथों में पहले से लिखा है, बस समझने और अपनाने की जरूरत है।'

धीरे-धीरे उन्होंने ऐसे उत्पाद बनाए जो आसपास के लोगों को लाभ देने लगे और रंग बहादुर किसान से गांव के वैद्य के रूप में प्रसिद्ध हो गए।

अमोरा बना लोक आयुर्वेद की प्रयोगशाला

रंग बहादुर की प्रेरणा से अमोरा गांव में तीन सौ से अधिक किसान आज औषधीय खेती कर रहे हैं।

यहां शतावरी, अश्वगंधा, अनार, चंदन, ड्रैगन फ्रूट और कटहल की खेती हो रही है। साथ ही, पोस्ट हार्वेस्टिंग यूनिट और प्रोसेसिंग फैसिलिटी भी स्थापित की गई है। उनके बेटे जनार्धन ने IIT-BHU के इनक्यूबेशन सेंटर से तकनीकी प्रशिक्षण लेकर हर्बल उत्पादों का निर्माण शुरू किया है। उन्हें एफएसएसएआई से लाइसेंस भी प्राप्त हो चुका है।

■ रंग बहादुर अपने बनाए गए औषधीय उत्पादों की निर्माण विधियां, संसाधन और फार्मूले अन्य किसानों से साझा करते हैं।

वे गांव के युवाओं को सिखाते हैं कि कैसे स्थानीय जड़ी-बूटियों से गुणवत्तापूर्ण, प्रभावशाली और बाजार में बिकने योग्य उत्पाद बनाए जा सकते हैं।

उनकी शोधशाला आज ज्ञान के साथ-साथ आत्मनिर्भरता की पाठशाला बन चुकी है।

■ वर्ष 2019 में क्षेत्रीय एवं सुगमता केंद्र उत्तर भारत-1 (RCFCNR-1) ने एक विशेष आग्रह पर अमोरा गांव में ग्रामीण परिवेश में रुककर तीन दिवसीय औषधीय कृषिकरण कार्यशाला आयोजित करने का निर्णय लिया। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से सैकड़ों हितग्राही, वैद्य, किसान, उद्योग प्रतिनिधि और नीति विशेषज्ञ शामिल हुए। ग्रामीण परिवेश में पहली बार आयोजित इस संवाद ने 'अमोरा शोधशाला' की नींव रखी। यहीं से यह गांव सिर्फ खेती का केंद्र नहीं रहा, बल्कि लोक आयुर्वेद के नवाचार, प्रशिक्षण और जमीनी शोध की पहचान बन गया।

नीतिगत परिवर्तन-जब किसान की आवाज बनी दिशा

उत्तर प्रदेश में औषधीय खेती पहले कृषि और उद्यान विभागों के अधीन थी, जिससे किसानों को सहयोग में कठिनाइयां आती थीं।

रंग बहादुर के नेतृत्व में हुई पहल के बाद अब इस विषय को आयुष विभाग के अंतर्गत लाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिससे औषधीय कृषिकरण को नया बल मिल रहा है।

पायलट मॉडल, प्रमाणन और कीमत - किसानों की नई मांग

आज आवश्यकता है कि देश में औषधीय पौधों की उन्नत किस्मों को मल्टी-लोकेशन ट्रायल्स के माध्यम से स्थानीय जलवायु के अनुरूप प्रमाणित किया जाए। इससे क्षेत्रीय 'प्रोडक्शन कॉरिडोर' विकसित किए जा सकते हैं। औद्योगिक इकाइयों को किसान समूहों के साथ साझेदारी में आना चाहिए और कच्चे माल के लिए न्यूनतम सुनिश्चित मूल्य तय किया जाना चाहिए।

रंग बहादुर कहते हैं, 'बीज की गुणवत्ता की प्रमाणिकता और किसानों को उनकी मेहनत का मूल्य मिले, यही असली आयुर्वेदिक क्रांति है।'

अमोरा से उठती लोक आयुर्वेद की लहर

डॉ. अरुण चंदन, क्षेत्रीय निदेशक (उत्तर भारत), का कहना है कि कोविड ने हमें लोक ज्ञान की ओर लौटने का अवसर दिया है। अमोरा गांव जैसी ग्रामीण शोधशालाएं पारंपरिक चिकित्सा के उन सूत्रों को पुनः स्थापित कर सकती हैं, जो कभी जनजीवन का हिस्सा हुआ करते थे। रंग बहादुर की शोधशाला न केवल एक किसान की जिजीविषा है, बल्कि एक जन आंदोलन की शुरुआत भी है, जहां खेती, ज्ञान और स्वास्थ्य एक साथ चलते हैं।

लाहौल का हर्बल व्यापार : सतत् आजीविका और टिकाऊ रोजगार, ग्रामीण आर्थिकी का आधार

आरसीएफसी नेटवर्क/लाहौल स्पीति

लाहौल घाटी के उदयपुर उपमंडल के नालडा गांव का 'हिमालय उच्च शिखरीय उत्पाद' महिला समूह स्थानीय जंगलों में उगने वाली दिव्य जड़ी-बूटियों से पारंपरिक ज्ञान के जरिए हर्बल उत्पाद बनाकर सतत् आजीविका और सैंकड़ों महिलाओं के लिए घर के पास रोजगार प्रदान कर स्थानीय समुदायों के लिए आर्थिकी के अवसर पैदा कर रहा है। ये कबायली महिलाएं राष्ट्रीय औषध पादप बोर्ड के क्षेत्रीय एवं सुगमता केंद्र उत्तर भारत-1, जोगिंद्रनगर के महत्वपूर्ण सहयोग से उद्यमशीलता का नया मुहावरा गढ़ रही हैं।

अपने औषधीय व पोषण गुणों के लिए मशहूर स्थानीय जंगलों में पैदा होने वाले सी बकथॉर्न, गुरनू, काला जीरा, शिलाजीत, आर्टेमिसिया, चौरा, रतनजोत, कुठ, मनु, रोज हिप तथा गुच्छी मशरूम से हर्बल उत्पाद बना कर यह महिला समूह हिमालयी हर्बल व्यापार में महिलाओं की भूमिका को मजबूत बना रहा है।

'हिमालय उच्च शिखरीय उत्पाद' समूह का गठन

'हिमालय उच्च शिखरीय उत्पाद' महिला समूह की अध्यक्ष अनीता नलवा का कहना है कि इस महिला समूह से 10 महिलाएं जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा पंचायत में विलेज ओर्गेनाइजेशन बनाई गई है, जिसमें 150 महिलाएं शामिल हैं, जो इस महिला समूह के लिए जड़ी-बूटियों की वाइल्ड कलेक्शन करती हैं। ये महिलाएं जड़ी-बूटियों के जानकार गांव के ही एक बुजुर्ग के मार्गदर्शन में वैज्ञानिक तरीके से जंगलों से जड़ी-बूटियां इक्ट्ठी करती हैं। गांव में जड़ी-बूटियों को प्रोसेस कर हर्बल प्रोडक्टस तैयार किए जाते हैं।

साल 2022 में क्षेत्रीय एवं सुगमता केंद्र उत्तर भारत-1, जोगिंद्रनगर ने आर्थिक गतिविधियों में कबायली महिलाओं की भागीदारी मजबूत करने के लिए 'हिमालय उच्च शिखरीय उत्पाद' महिला समूह के गठन और पंजीकरण में मदद की। इसके बाद इस समूह ने उच्च मूल्य वाले औषधीय और सुगंधित पौधों का संग्रहण करने, उनके उत्पाद बनाने और बिक्री में कदम रखा।

क्षेत्रीय एवं सुगमता केंद्र का सहयोग

'हिमालय उच्च शिखरीय उत्पाद' महिला समूह की उल्लेखनीय उपलब्धियों में क्षेत्रीय एवं सुगमता केंद्र के मार्गदर्शन और सहायता की अहम भूमिका रही है। इस सुगमता केंद्र ने समूह के पंजीकरण में सहायता कर इस समूह को औपचारिक मान्यता प्रदान कर घाटी में जड़ी-बूटियों की खेती और टिकाऊ संग्रह को बढ़ावा दिया।

अच्छे कृषि अभ्यास (जीएपी) और अच्छे क्षेत्र संग्रहण अभ्यास (जीएफसीपी) के पालन को सुनिश्चित कर सुगमता केंद्र ने इस समूह को तकनीकी परामर्श, गुणवत्ता नियंत्रण, मूल्य संवर्धन और बाजार संबंधों को समझने में मदद की है।

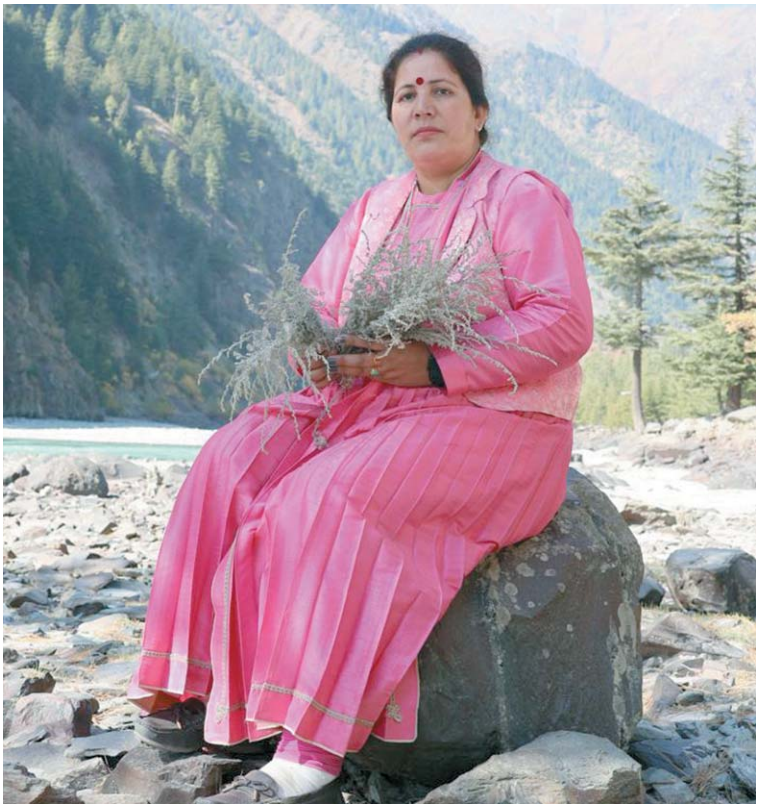

शोधकर्ताओं और उद्यमियों के साथ समूह के मजबूत संबंध

'हिमालय उच्च शिखरीय उत्पाद' महिला समूह की अध्यक्ष अनीता नलवा ने 1 से 6 सितंबर, 2024 तक क्षेत्रीय एवं सुगमता केंद्र उत्तर भारत-1, जोगिंद्रनगर और इंस्टीट्यूट ऑफ मेनेजमेंट की संयुक्त शोध यात्रा में भाग लिया। इस यात्रा के दौरान उन्होंने शोधकर्ताओं और उद्यमियों के साथ संबंधों को मजबूत किया। उन्होंने 28 से 31 दिसंबर 2024 तक अहमदाबाद में सृष्टि द्वारा आयोजित 'सात्विक-पारंपरिक खाद्य महोत्सव' में भाग लिया, जहां उन्होंने विविध और व्यापक दर्शकों के लिए हिमालयी हर्बल उत्पादों को प्रदर्शित किया।

अनीता नलवा ने 10 से 19 जनवरी, 2025 तक शिमला में आयोजित एक प्रदर्शनी में अपने स्वयं सहायता समूह का प्रतिनिधित्व करते हुए समूह के हर्बल उत्पादों को प्रदर्शित कर वाहवाही लूटी। दिल्ली में आदि महोत्सव 2025 में 'हिमालय उच्च शिखरीय उत्पाद' महिला समूह ने सहयोग और विकास को बढ़ावा देने के लिए अन्य स्वयं सहायता समूहों के साथ एमओयू साइन कर अपनी पहुंच को विस्तार दिया।

उद्यम में बदला पारंपरिक हर्बल ज्ञान

पहले हर साल नवंबर माह में लाहौल घाटी का यह इलाका पूरी तरह से दुनिया से कट जाता था। अटल टनल रोहतांग ने साल भर इस क्षेत्र को दुनिया से जोड़ने का काम किया है। क्षेत्रीय एवं सुगमता केंद्र उत्तर भारत-1 के सही और संस्थागत समर्थन से अनीता नलवा ने रोहतांग टनल के शुरू होने का लाभ उठाते हुए ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने और स्थाई आजीविका के प्रबंधन में स्वयं सहायता समूह की क्षमता का अनूठा उदाहरण पेश किया है। उन्होंने पारंपरिक हर्बल ज्ञान को एक संपन्न उद्यम में बदल दिया है।

जैसे-जैसे अनीता नलवा के नेतृत्व में 'हिमालय उच्च शिखरीय उत्पाद' महिला समूह अपनी पहुंच का विस्तार करता जाएगा, औषधीय कृषिकरण के क्षेत्र में महिलाओं के नेतृत्व वाली उद्यमिता के लिए एक प्रेरणादायक मॉडल विकसित होता जाएगा।

दो दशक के संघर्ष से निकली सफलता की राह

अनीता नलवा की सामाजिक उद्यमशीलता का सफर 2003 में निफ्ट कांगड़ा की सिक्योर हिमालय परियोजना से शुरू हुआ, जिसके तहत उन्होंने चंबा के पांगी में 45 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया। 2021-22 में उन्होंने लाहौल में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में गहन क्लस्टर रिर्सोस पर्सन के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अनीता नलवा ने स्थानीय महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए स्वयं सहायता समूहों, ग्राम संगठनों और जागरूकता शिविरों के गठन में अहम योगदान दिया है।

पांगी और लाहौल में कारीगरों की क्षमता को पहचानते हुए उन्होंने निफ्ट कांगड़ा के साथ एक अन्य परियोजना में सहयोग किया, जिसके चलते यहां की महिलाओं को कारीगर कार्ड जारी करने की सुविधा प्रदान की। इससे उन्हें पहचान मिली और बेहतर बाजार के अवसरों तक पहुंच हुई। इससे कबायली महिलाओं का हुनर, नाबार्ड, ट्राइब्स इंडिया, निफ्ट कांगड़ा, राज्य संग्रहालय शिमला, हिमकॉस्ट और हथकरघा विभाग के लिए स्टॉल लगाने तक फैल गया।

जैविक संसाधनों के वैज्ञानिक और टिकाऊ दोहन का सवाल

जैव विविधता संरक्षण के लिए लाहौल घाटी में कार्य करने वाले उदयपुर से संबंध रखने वाले तोद चंद ठाकुर चिंता जाहिर करते हुए कहते हैं कि जनजातीय क्षेत्र में जैविक संसाधनों से प्राकृतिक उत्पाद बनाने से संबन्धित छुट-पुट जो भी महिलाएं कार्य कर रहीं हैं, उसके चलते पिछले कुछ सालों में यहां बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। व्यापारी किस्म के लोग सीधे लोगों से जड़ी-बूटियां खरीदने लगे हैं। इससे जैविक संसाधनों से प्रकृतिक उत्पाद बनाने वाले महिला समूहों को जड़ी- बूटियां खरीदने का संकट पैदा होने लगा है।

जैव संसाधनों को सीधे लोगों से खरीदने वाले थोड़ा बहुत अग्रिम भुगतान करते हैं। कई बार जड़ी-बूटियां उठा लेते हैं, कई बार उठाते नहीं हैं। कई बार औषधीय कृषिकरण में जुटे लोगों के साथ धोखा हो जाता है।

तोद चंद ठाकुर कहते हैं कि जनजातीय क्षेत्रों के जैविक संसाधनों के वैज्ञानिक और टिकाऊ दोहन के लिए जैविक विविधता अधिनियम 2002 का अनुपालन होना जरूरी है।

इसके लिए सरकार को अटल टनल रोहतांग पर चेक पोस्ट स्थापित करनी चाहिए और 2010 के नगोया प्रोटोकोल के तहत ही जैविक संसाधनों को लाहौल घाटी ले बाहर ले जाने की अनुमति दी जानी चाहिए।

एमपी के नीमच की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश के ऊना में बननी चाहिए जड़ी-बूटियों की मंडी

■ बल्क ड्रग पार्क के लिए आसानी से उपलब्ध होगी रॉ मैटीरियल

■ औषधीय खेती करने वालों को मिलेगा उनकी उपज का उचित दाम

आरसीएफसी नेटवर्क/हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला में बल्क ड्रग पार्क जैसी बड़ी परियोजना का निर्माण हो रहा है। अब देश भर में बनने वाली दवाईयों के लिए कच्चा माल यहां तैयार होगा। जाहिर है कि एलोपैथी की दवाईयां के साथ आयुर्वेदिक दवाईयों के लिए भी यहां कच्चा माल तैयार होगा। आयुर्वेदिक दवाईयां के निर्माण के लिए प्रयोग होने वाला कच्चा माल जड़ी-बूटियां से तैयार होता है। ऐसे में ऊना में बनने वाला बल्क ड्रग पार्क आयुर्वेदिक दवाईयां के कच्चे माल के लिए भी एक बहुत बड़ा स्थान हो सकता है। तीस साल तक मध्य-प्रदेश में औषधीय कृषिकरण को लेकर जमीनी स्तर पर काम करने वाले ऊना जिला के नंगल जरयाला निवासी गुरपाल सिंह कहते हैं कि जड़ी- बूटियों को बेचने का उचित प्रबंधन किए बिना औषधीय कृषिकरण को सतत् आजीविका और रोजगार का मॉडल बनाना मुमकिन नहीं है। उनका कहना है कि हिमाचल प्रदेश के सभी जड़ी-बूटी उत्पादकों को एक छत के नीचे आकर प्रदेश सरकार से जड़ी-बूटियों की बिक्री के लिए मंडी स्थापित करने की मांग करनी चाहिए।

गुरपाल सिंह कहते हैं कि ऊना में बन रहे बल्क ड्रग पार्क में आयुर्वेदिक दवाईयां के लिए कच्चे माल का उत्पादन करने के लिए जड़ी-बूटियां की आसानी से उपलब्धता जरूरी है। हिमाचल प्रदेश दिव्य-जड़ी बूटियों की भूमि है। प्रदेश के जंगलों में बहुत सी बहुमूल्य जड़ी-बूटियां प्राकृतिक तौर पर पैदा होती हैं। कुछ सालों से हिमाचल प्रदेश के किसान जड़ी-बूटियां की खेती के प्रति आकर्षित हुए हैं। ऊना जिला में स्थापित हो रहे बल्क ड्रग पार्क में आयुर्वेदिक दवाईयों के कच्चे माल के उत्पादन के लिए घर के पास औषधीय उपज उपलब्ध हो, इसके लिए मध्य प्रदेश के नीमच में स्थापित मंडी की तर्ज पर ऊना में जड़ी-बूटियों की मंडी स्थापित की जानी चाहिए।

बल्क ड्रग पार्क और मिशन धनवंतरी

गुरपाल सिंह कहते हैं कि बल्क ड्रग पार्क में आयुर्वेदिक दवाईयां के निर्माण के लिए भी कच्चा माल तैयार करने वाले यूनिट्स भी स्थापित करने की दिशा में सरकार को प्रयास करने चाहिए। सरकार को चाहिए कि बल्क ड्रग पार्क में आयुर्वेद दवा निर्माण के लिए एपीआई बनाने वाली देश-विदेश की कंपनियों को निवेश के लिए आमंत्रित किया जाए। ऐसी यूनिट्स के लिए जहां रॉ मैटीरियल घर के पास आसानी से उपलब्ध होगा, वहीं औषधीय कृषिकरण करने वाले किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए भी सुविधा होगी।

वे कहते हैं कि प्रदेश के आयुर्वेदिक विभाग और ग्रामीण विकास विभाग ने हिमाचल प्रदेश में मिशन धनवंतरी के अंतर्गत जड़ी-बूटियां की खेती को मनरेगा में शामिल कर पहल की है। इस मुहिम के चलते प्रदेश में बड़े स्तर पर किसान जड़ी-बूटियां की खेती कर रहे हैं। ऐसे में जरूरत है कि किसानों द्वारा उत्पादित जड़ी-बूटियों को बेचने की उचित व्यवस्था हो। जड़ी-बूटी मंडी में किसानों को उनकी फसल का उचित दाम मिल सकेगा।

सरकारी परचेज में स्थानीय किसानों को मिले प्राथमिकता

गुरपाल सिंह कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में स्थापित सरकारी फार्मेसीज में बहुत से कच्चे माल की खरीद की जाती है। सरकारी खरीद के नियम इतने कड़े हैं कि इसमें स्थानीय जड़ी-बूटी उत्पादक भाग नहीं ले पाते हैं। ऐसे में प्रदेश में संचालित होने वाली सरकारी फार्मेसीज के लिए कच्चे माल की खरीद हिमाचल प्रदेश के बाहर की कंपनियों से ही की जाती है।

उनका कहना है कि सरकारी खरीद के लिए नियमों में डील देनी चाहिए और प्रदेश के औषधीय कृषिकरण करने वाले किसानों को ऐसी सरकारी खरीद में न केवल शामिल किया जाना चाहिए, बल्कि प्राथमिकता मिलनी चाहिए।

जागरूकता से जोर पकड़ेगी जड़ी-बूटियों की खेती

गुरपाल सिंह किसानों को गाइड करते हैं कि किस जड़ी-बूटी की बाजार में भारी मांग है और किसकी अच्छी कीमत मिल रही है। वे किसानों को जड़ी-बूटियों की प्रोसेसिंग में भी मदद करते हैं। वे कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में ऐसी कोई इंडिपेंडेंट संस्था होनी चाहिए जो जड़ी-बूटियों की खेती करने वाले किसानों को क्वालिटी प्लांटिंग मैटीरियल से लेकर प्रोसेसिंग और मार्केटिंग में उनका सहयोग करें।

किसानों को यह सूचना भी समय-समय पर मिलती रहनी चाहिए कि किस जड़ी-बूटी को उगाकर उनको फायदा मिल सकता है। वे कहते हैं कि जागरूकता के बाद ही किसान उच्च कीमत वाली जड़ी-बूटियों की खेती की ओर अग्रसर होंगे और किसानों को अपनी उपज का अच्छा दाम मिलेगा। उनकी चिंता है कि अगर किसानों को बाजार सुविधा नहीं मिलती है तो आने वाले समय में वे जड़ी-बूटियां की खेती से मुंह मोड़ सकते हैं।

पहाड़ की जड़ी-बूटियां की भारी मांग

गुरपाल सिंह का कहना है कि हिमाचल प्रदेश में उच्च मूल्य वाली दिव्य जड़ी-बूटियां पैदा होती हैं। गुणवत्ता के मामले में हिमाचल प्रदेश में पैदा होने वाली जड़ी-बूटियां देश के दूसरे स्थानों पर पैदा होने वाली जड़ी-बूटियों से बहुत आगे हैं। प्रदेश के जंगलों में पैदा होने वाली और खेतों में उगाई जाने वाली जड़ी-बूटियों की देश-विदेश के बाजार में भारी मांग रहती है। ऐसे में जरूरी है कि हिमाचल प्रदेश में पैदा होने वाली जड़ी-बूटियों को एक बड़े ब्रांड के अंतर्गत ही बेचा जाए। तभी इन जड़ी-बूटियां की अच्छी कीमत किसानों को मिल सकती है।

वे कहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस बात का प्रचार-प्रसार होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में कौन-कौन सी जड़ी-बूटियां पैदा हो रही हैं और कितनी मात्रा में पैदा होती हैं। वे कहते हैं कि यह भी जरूरी हैं कि प्रदेश के सभी जड़ी-बूटी उत्पादक एक छत के नीचे आएं, तभी औषधीय कृषिकरण की दिशा में किसान आगे बढ़ेंगे।

ऊना के लाल ने किया मध्य प्रदेश में कमाल

कई राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के साथ काम कर चुके गुरपाल सिंह ने मध्य प्रदेश में जड़ी-बूटियां की खेती, उनकी प्रोसेसिंग तथा उसकी बिक्री के लिए तीन दशक तक कार्य किया है। गुरपाल सिंह ने उस राज्य में 25,000 से ज्यादा किसानों को जड़ी-बूटियां की खेती के लिए प्रशिक्षित किया है। उनके प्रशिक्षित किए हुए 1500 ऐसे किसान हैं, जो वर्तमान में न केवल जड़ी-बूटियां की खेती कर रहे हैं, बल्कि उनकी प्रोसेसिंग कर उन्हें बेच रहे हैं।

गुरपाल सिंह अब अपने पैतृक गांव नंगल जरयाला में रहते हैं और औसत पादप बोर्ड के क्षेत्रीय सुविधा केंद्र की मदद से अपने क्षेत्र में जड़ी-बूटियों की खेती कर रहे हैं। उन्होंने अपनी पैतृक जमीन पर अशोक और अमलतास के पौधे लगाए हुए हैं। वे न केवल अपने खेतों में कई तरह की जड़ी-बूटियां उगाने के प्रयोग कर रहे हैं, बल्कि क्षेत्र में औषधीय कृषिकरण की तरफ मुड़े किसानों को गाइड भी कर रहे हैं।

हर घर नीम - एक मुहिम
आरसीएफसी के सहयोग से शिक्षक का मिशन

आरसीएफसी नेटवर्क/हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश में तीन साल पहले एक प्राइमरी स्कूल टीचर के ईमानदार प्रयासों से स्कूली बच्चों के सहयोग से शुरू हुआ 'हर घर नीम' कार्यक्रम अब एक मुहिम का रूप धारण कर चुका है। कांगड़ा जिला के प्राइमरी स्कूल बंडोल के राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान से पुरस्कृत सुनील कुमार ने अपने स्कूल से इम मुहिम की पहल की। नीम लगाने के इस मिशन में स्टूडेंट्स और उसके अभिभावक भावनात्मक रूप से बंध गए और सभी स्टूडेंट्स के खेतों में नीम उग गया।

सुनील कुमार हर घर नीम की इस मुहिम को प्रदेश के अधिकतर घरों तक ले जाने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं और विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से सारे प्रदेश में इस ड्राइव के लिए प्रयासरत हैं। पर्यावरण संरक्षण एवं जागरूकता की इस मुहिम के लिए इस साल विश्व पर्यावरण दिवस पर बंडोल स्कूल को राज्य पर्यावरण लीडरशिप पुरस्कार प्रदान किया गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने शिक्षक सुनील कुमार को सतत् शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया है। औषध पादप बोर्ड के क्षेत्रीय एवं सुगमता केंद्र ने सुनील कुमार को नीम का क्वालिटी प्लांटिंग मैटीरियल उपलब्ध करवाया है।

'सेल्फी विद नीम' से ग्राउंड रिपोर्ट

अपने स्कूल के अलावा अब तक सुनील कुमार प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में दो हजार से ज्यादा नीम के पेड़ लगवा चुके हैं। अब अर्थ जस्ट फाउंडेशन और हिमकॉस्ट सहित कई संस्थाएं उनकी इस मुहिम में शामिल हैं। सुनील कुमार बताते हैं कि नीम का कोई पौधा देखभाल के बिना सूखे न, इसके लिए उन्होंने सोशल मीडिया पर 'सेल्फी विद नीम' शुरू किया है।

सुनील कुमार बताते हैं कि नीम का पौधा उसी को उपलब्ध करवाया जाता है, जो पौधरोपण को लेकर गंभीर हो। समय-समय पर नीम लगाने वाले को 'सेल्फी विद नीम' के जरिये अपने पौधे की ग्रोथ के बारे में सूचित करना होता है। इससे पौधे की ग्रोथ को लेकर अपडेट मिलती रहती है।

नीम का क्वालिटी प्लांटिंग मैटीरियल

सुनील कुमार का कहना है कि हर घर नीम की पहल उन्होंने अपने खुद के संसाधनों से की थी। इस मुहिम को धीरे-धीरे कई संस्थाओं का सहयोग मिलता गया। औषध पादप बोर्ड के क्षेत्रीय सुगमता केंद्र उत्तर भारत, जोगिंद्रनगर ने नीम का उच्च गुणवता वाला क्वालिटी प्लांटिंग मैटीरियल उपलब्ध करवाया, जिससे 'हर घर नीम' मुहिम को गति मिली। हिमाचल प्रदेश में नीम परिवार के सदस्यों की संख्या दो हजार से ज्यादा हो चुकी है। इस बार भी नीम के हजारों रोपने का टार्गेट रखा गया है। हर घर नीम सहित पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता की नवाचारी गतिविधियों के लिए सुनील कुमार पूरी तरह से समर्पित हैं।

नीम मैन के मान से बुलाने लगे लोग

बंदोल स्कूल प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों के लिए मॉडल स्कूल है। डिजिटल इंडिया के तहत प्राईमरी स्कूल में डिजिटल तरीके से ही बच्चों को बिना किताबों और नोटबुक्स के अध्ययन करवाया जा रहा है। स्कूल में स्मार्ट क्लासरूम, वाई-फाई, इंग्लिश मीडियम पढ़ाई, वीडियो कांफ्रेंस सुविधा है। इस स्कूल का अपना हर्बल गार्डन भी है। स्कूल में औषधीय पौधों के साथ-जैविक खेती करते हुए सब्जियां तैयार करके मिड-डे मील में इस्तेमाल में लाई जा रही हैं। स्कूल के स्टूडेंट्स को अब औषधीय कृषिकरण की दिशा में जागरूक करने की अनूठी पहल ने शिक्षक सुनील कुमार आयुष का राजदूत बना दिया है। उन्हें लोग नीम बांटने वाला टीचर और नीम मैन भी कहने लगे हैं।

शिक्षक के प्रयासों का सम्मान

वर्ष 2024 में शिक्षक दिवस पर सुनील कुमार को नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया और उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात का भी अवसर मिला। सुनील कुमार को इंटरनेशनल स्कूल अवार्ड के तहत चंडीगढ़ में इनोवेटिव टीचर अवार्ड पुरस्कार भी मिला है। कई सामाजिक संस्थाएं भी सुनील कुमार को सम्मानित कर चुकी हैं।

वर्ष 2000 से शिक्षा विभाग में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे सुनील कुमार ने बीएससी, डिप्लोमा इन सिविल इंजिनियरिंग और डिप्लोमा इन स्पेशल एजूकेशन किया है। वे आपदा प्रबंधन को लेकर भी कार्य करते आ रहे हैं।

प्रधानमंत्री मोदी भी हैं सुनील के फैन

पिछले साल जब सुनील कुमार को शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उनसे मुलाकात की थी। शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर सम्मानित शिक्षकों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने शिक्षक सुनील कुमार की जमकर तारीफ की थी। प्रधानमंत्री ने तब कहा था कि शिक्षा के क्षेत्र में उनके प्रयास न केवल प्रेरक हैं, बल्कि नवोदित भी हैं। सुनील कुमार ने 'हर घर नीम' मुहिम को लेकर केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) प्रताप राव जादव से मुलाकात कर इस बारे में सूचित किया है। स्कूल स्टूडेंट्स को साथ लेकर पहाड़ पर नीम की खेती को मुहिम में बदलने वाले इस शिक्षक की इस पहल पर केंद्रीय मंत्री ने उनकी पीठ थपथपाई है और उन्हें प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया है। अध्यात्मिक गुरु श्री रविशंकर की संस्था भी सुनील कुमार को नवाचार के लिए सम्मानित कर चुकी है।

उम्र हो गई अस्सी साल, हर्बल खेती से किया कमाल

सिंचाई सुविधाओं के अभाव के बीच बंजर जमीन पर औषधीय खेती कर रहे नगरोटा बगवां के रिटायर्ड टीचर रमेश कुमार

आरसीएफसी नेटवर्क/हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला के नगरोटा बगवां उपमंडल के चंगर क्षेत्र की बराना पंचायत के अस्सी साल के रिटायर्ड टीचर रमेश कुमार औषधीय कृषिकरण में कमाल कर रहे हैं। बंजर जमीन पर सिंचाई सुविधाओं के अभाव के बावजूद जिद और जुनून से उन्होंने हरियाली रोपने के लिए खूब पसीना बहाया है। जब इस प्रदेश ने औषधीय कृषिकरण के बारे में सुना तक नहीं था, रमेश कुमार उस समय से जड़ी-बूटियां उगाते आ रहे हैं। औषधीय कृषिकरण और प्रोसेसिंग में उनके पास 35 साल का अनुभव है। वे शतावरी, अश्वगंधा, बृंगराज, पुनर्रवा, कई प्रकार की हल्दी, एलोवेरा और मोरिंगा की खेती कर रहे हैं। वे मोरिंगा की खेती बड़े स्तर पर करने जा रहे हैं।

रमेश कुमार बागवानी भी करते हैं। उनका गलगल, नींबू और माल्टा का बाग है। उन्होंने अपने बाग में कॉफी के भी चालीस पौधे तैयार किए हैं।

औषध पादप बोर्ड के जोगिंद्रनगर स्थित क्षेत्रीय एवं सुगमता केंद्र के विशेषज्ञ उन्हें जड़ी- बूटियों का क्वालिटी प्लांटिंग मैटीरियल उपलब्ध करवाने के साथ औषधीय कृषिकरण को लेकर महत्वपूर्ण सुझाव भी देते हैं।

जड़ी-बूटियों से खुद बनाते आयुर्वेदिक दवाईयां

रमेश कुमार को औषधीय पौधों के गुणों की गहरी समझ है और प्रोसेसिंग का लंबा अनुभव। वे वैद्य के तौर पर जाने जाते हैं और जड़ी-बूटियों से उपचार करते हैं। जड़ी-बूटियों की खेती वे अपने प्रयोग के लिए करते हैं। वे जड़ी बूटियों को बाजार में नहीं बेचते। 35 साल से जड़ी बूटियों की खेती कर रमेश कुमार जोड़ों के दर्द की दवा और गठिया के दर्द की दवा सहित कई तरह के दर्द निवारक बनाते हैं। वे आंबला पाउडर बनाते है और बेहड़ा से थाईरायड के उपचार के लिए दवाई बनाते हैं। हरड़ से भी वे दवाईयां बनाते हैं।

खेतों को पानी, सबसे बड़ी परशानी

रमेश कुमार की पंचायत में पानी का अभाव है। सिंचाई के लिए पानी की परेशानी के चलते उन्होंने अपने खेतों में रेन हार्वेस्टिंग के लिए तालाब बनाया है, जहां बारिश के पानी को इकट्ठा किया जाता है। उन्होंने खेतों के साथ बहते नाले पर चेक डैम बनाया है, जहां गर्मियों में भी पानी रहता है।

उनके जीवट को देखते हुए स्थानीय पंचायत ने उनके खेत में पानी का एक टैंक और शेड बनाने के लिए प्रस्ताव पारित किया है। उनका कहना है कि उनके खेत में बोर कर पंप लगाकर सिंचाई सुविधा का समाधान हो, तभी उनका औषधीय कृषिकरण का मॉडल कामयाब हो सकता है।

खेतों में काम करे युवा

रमेश कुमार का कहना है कि खेतों में काम करने के लिए स्थानीय लोग गंभीर नहीं हैं। उनका कहना है कि अगर युवा अपने खेतों में औषधीय पौधों की खेती करें तो कृषि आर्थकी को मजबूत किया जा सकता है।

उनका कहना है कि व्यवसायिक स्तर पर औषधीय कृषिकरण के लिए काम करने वाले मजदूरों की कमी के चलते लोग जड़ी- बूटियों की खेती को लेकर ज्यादा उत्साहित नहीं है। धुन के पक्के रमेश कुमार औषधीय कृषिकरण के मिशन में डटे हैं। हालांकि उन्हें भी अपने मिशन के लिए खेतों में काम करने वाले मजदूरों की समस्या का सामना करना पड़ता है। उनका कहना है कि औषधीय कृषिकरण से बड़े स्तर पर रोजगार सृजन किया जा सकता है।

चुनौतियों के हों समाधान, जड़ी-बूटियां बनेंगी वरदान

ग्लोबल हर्बल बास्केट बनने के लिए भारत को मजबूत करनी होगी मेडिसनल प्लांट्स की वैल्यू चेन

आरसीएफसी नेटवर्क/हिमाचल प्रदेश

भारत विश्व की उन प्राचीन सभ्यताओं में से है, जहां चिकित्सा पद्धति में औषधीय पौधों का स्थान सर्वोपरि रहा है। आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी, होम्योपैथी, सोवा-रिग्पा जैसी परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों में औषधीय पौधों की लगभग 2500 प्रजातियां उपयोग में लाई जाती हैं। भारत की विविध जलवायु और पारंपरिक ज्ञान संपदा ने इसे औषधीय पौधों की दृष्टि से एक समृद्ध देश बना दिया है।

बढ़ती वैश्विक मांग और स्वास्थ्य जागरूकता के बीच यह आवश्यक हो गया है कि हम औषधीय पौधों की मूल्य श्रृंखला को सशक्त बनाएं, उसकी वर्तमान चुनौतियों की पहचान करें और उनके व्यावहारिक समाधान प्रस्तुत करें।

औषधीय पौधों की मूल्य श्रृंखला

औषधीय पौधों की मूल्य श्रृंखला (Medicinal Plants Value Chain) में निम्नलिखित मुख्य चरण आते हैं।

1. बीज और रोपण सामग्री की उपलब्धता (QPM)
2. खेती व वैज्ञानिक कृषि पद्धति (GAP)
3. वन्य संग्रहण व GFCP प्रक्रिया
4. पोस्ट हार्वेस्ट प्रबंधन
5. प्रसंस्करण व उत्पाद विकास
6. विपणन व ब्रांडिंग
7. नीति, अनुसंधान व प्रशिक्षण सहयोग

प्रमुख चुनौतियां

1. गुणवत्ता युक्त बीज एवं रोपण सामग्री की कमी
2. प्रमाणित नर्सरियों और बीज स्रोतों की कमी।
3. फॉरेस्ट आधारित पौधों की बीज संग्रहण प्रणाली विकसित नहीं।
4. क्षेत्रीय प्रजातियों की बहुवर्षीय जांच का अभाव।

संभावित समाधान

1. राष्ट्रीय स्तर पर मॉडल नर्सरी अधिनियम बनाकर क्रियान्वयन।
2. बीज बैंक की स्थापना और बीज प्रमाणन की पारदर्शी व्यवस्था।
3. नेटवर्क आधारित नर्सरी मॉडल का विकास।

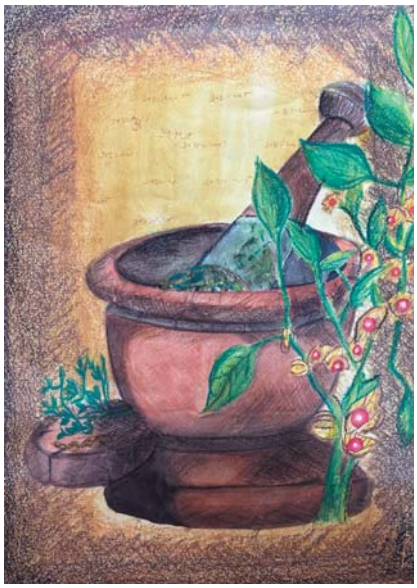

वैज्ञानिक खेती की सीमाएं

1. वैज्ञानिक खेती की जानकारी का अभाव।
2. किसान प्रशिक्षण में एकरूपता नहीं।
3. जैविक प्रमाणीकरण प्रक्रिया जटिल व महंगी।

संभावित समाधान

1. क्लस्टर आधारित वैज्ञानिक खेती प्रमाणीकरण योजना।
2. मोबाइल एप और क्षेत्रीय भाषा में प्रशिक्षण मैनुअल का प्रचार।
3. सस्ते प्रमाणीकरण के लिए सामूहिक योजनाएं।

वन्य संग्रहण को लेकर समस्याएं

1. संग्रहण का समय, विधि और स्थान मानकों के अनुरूप नहीं।
2. वनों से संग्रहण हेतु जटिल अनुमति प्रक्रिया।
3. ट्रेसेबिलिटी और बीएमसी के साथ समन्वय की कमी।

संभावित समाधान

1. GFCP आधारित संग्रहण के लिए प्रशिक्षण एवं प्रमाणन।
2. BMC को सशक्त करना और उनके माध्यम से संग्रहण निगरानी।
3. सामुदायिक वन प्रबंधन और स्थानीय वन उपयोग अधिकारों का संरक्षण।

पोस्ट हार्वेस्ट प्रबंधन और तकनीकी अंतराल की चुनौतियां

1. किसानों के पास ग्रेडिंग, ड्रायिंग और संग्रहण की वैज्ञानिक तकनीक नहीं।
2. खराब भंडारण से गुणवत्ता में हानि।
3. प्रोसेसिंग केंद्रो की कमी।

संभावित समाधान

1. प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्रों की स्थापना (शीतगृह, ड्रायर)।
2. मंडी नेटवर्क में औषधीय पौधों की विशेष श्रेणी।
3. स्वयं सहायता समूह और FPO के माध्यम से प्रोसेसिंग यूनिट्स को प्रोत्साहन।

विपणन, मूल्यवर्धन और ब्रांडिंग की समस्याएं

1. किसान और खरीदार के बीच सीधा जुड़ाव नहीं।
2. औषधीय पौधों की मिनिमम सपोर्ट प्राइज व्यवस्था नहीं।
3. राष्ट्रीय स्तर पर ब्रांडिंग और जीआई टैगिंग की धीमी प्रक्रिया।

संभावित समाधान

1. राज्य स्तरीय औषधीय मंडियां और लाइव ऑनलाइन बोली प्रणाली।
2. औषधीय पौधों की मिनिमम सपोर्ट प्राइज और मूल्य समर्थन योजना।
3. जीआई टैगिंग के लिए दस्तावेजीकरण प्रक्रिया का सरलीकरण।

अनुसंधान, नवाचार और नीति निर्धारण की चुनौतियां

1. औषधीय पौधों पर विशेष अनुसंधान कम।
2. नीति में जमीनी भागीदारी और पारंपरिक ज्ञान का समावेश नहीं।
3. विभिन्न मंत्रालयों में समन्वय का अभाव।

संभावित समाधान

1. कृषि विश्वविद्यालयों, IITs, CCRAS, NMPB के साथ साझेदारी में अनुसंधान केंद्रो की स्थापना।
2. पारंपरिक वैद्य ज्ञान को वैज्ञानिक रूप से मान्यता देना।
3. केंद्रीय और राज्य मंत्रालयों के बीच एकीकृत नीति ढांचा।

वर्तमान प्रयासों की झलक

1. GAP व GFCP प्रमाणन प्रक्रिया में हिमाचल में 200 से ज्यादा किसान जुड़े।
2. गुणवतापरक बीज, पौध सामग्री, मृदा परीक्षण, सौर ड्रायर और अन्य तकनीकों पर प्रशिक्षण।
3. महिला स्वयं सहायता समूहों को मूल्यवर्धन के लिए प्रशिक्षित किया गया।
4. www.rcfcnorth.in पोर्टल और हेल्पलाइन के जरिए किसानों की सहायता।

नीतिगत सिफारिशें

1. राज्यवार औषधीय पौधों की मूल्य श्रृंखला नीति।
2. प्रमाणित QPM वितरण और नर्सरी नेटवर्क का सशक्तीकरण।
3. GFCP आधारित संग्रहण के लिए सामुदायिक प्रशिक्षण योजना।
4. औषधीय पौधों के लिए मूल्य समर्थन नीति और मंडी प्रावधान।
5. SHG और FPO आधारित उत्पाद विकास और स्थानीय ब्रांडिंग।
6. सामूहिक जीआई टैगिंग व IP संरक्षण के लिए त्वरित प्रक्रिया।

7. एकीकृत डिजिटल मंच (जन-किसान-प्रोसेसर) के विकास की आवश्यकता।

औषधीय पौधों का क्षेत्र भारत के पारंपरिक ज्ञान और जैव विविधता की शक्ति का प्रतीक है। औषधीय पौधों की समृद्ध विरासत, भारत की संस्कृति और स्वास्थ्य परंपरा का अभिन्न हिस्सा है। यदि इसकी मूल्य श्रृंखला में मौजूद चुनौतियों को रणनीतिक रूप से हल किया जाए, तो यह न केवल ग्रामीण भारत के लिए आजीविका के नए द्वार खोल सकता है, बल्कि वैश्विक हर्बल बाजार में भारत की भागीदारी को भी बढ़ा सकता है। इसके लिए सरकार,किसानों, शोध संस्थानों और नीति निर्माताओं के बीच समन्वय अत्यंत आवश्यक है।

जड़ी-बूटियों की खेती और संग्रहण के लिए प्रमाणित हिमाचल प्रदेश की पहली सोसायटी

आरसीएफसी नेटवर्क/हिमाचल प्रदेश

शिमला जिला के रोहड़ू उपमंडल की रोहल पंचायत की त्रिदेव औषधीय पौध उत्पादन सोसायटी जड़ी-बूटियों की अच्छी कृषि पद्धतियों (जीएपी) और अच्छी फील्ड संग्रहण पद्धतियों (जीएफसीपी) के लिए प्रमाणन हासिल करने वाला हिमाचल प्रदेश का पहला किसान समूह है। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के तहत कार्य करने वाले औषध पादप बोर्ड ने इस किसान समूह का जीएपी और जीएफसीपी के लिए फरवरी, 2027 तक प्रमाणीकरण किया है। जीएपी प्रमाणन के तहत कवर किया गया क्षेत्र 40 हेक्टेयर तक फैला है, जिसमें 94 किसान जड़ी-बूटियों की खेती कर रहे हैं। त्रिदेव औषधीय पौध उत्पादन सोसायटी के जनक कृपाल सिंह कहते हैं कि जड़ी-बूटियों की खेती और संग्रहण के लिए उनके समूह का प्रमाणीकरण औषधीय पौधों की स्थाई कृषि और क्षेत्र संग्रहण प्रथाओं के प्रति हमारी अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है।

त्रिदेव औषधीय पौध उत्पादन सोसायटी वन की ओर से प्रदान की गई 120 बीघा भूमि सहित सैंकड़ों बीघा निजी भूमि पर औषधीय खेती कर रही है। कृपाल सिंह बताते हैं कि त्रिदेव औषधीय पौध उत्पादन सोसायटी के अंतर्गत रोहड़ू उपमंडल के विभिन्न गांवों के 20 से अधिक समूह औषधीय पौधों की खेती कर आत्मनिर्भर बन रहे हैं। ये समूह केंद्र सरकार के आयुष मंत्रालय की जैव विविधता योजना, जायका व वन समृद्धि, जन समृद्धि योजनाओं के तहत काम करते हुए औषधीय खेती को बढ़ावा दे रहे हैं।

सोसायटी प्राकृतिक एवं औषधीय पौधों की खेती में सराहनीय कार्य कर रही है। औषध पादप बोर्ड के क्षेत्रीय सुगमता केंद्र ने इस सोसायटी को क्वालिटी प्लांटिंग मैटीरियल से लेकर इस किसान समूह का जीएपी और जीएफसीपी प्रमाणीकरण करवाने में सहयोग किया है।

हर्बल प्रोडक्टस की ऑनलाइन मार्केटिंग

त्रिदेव औषधीय पौध उत्पादन सोसायटी ने अब अपने उत्पादों को लोगों तक आसानी से पहुंचाने के लिए वेबसाइट www.tridevaushdhi.com लांच की है। इस वेबसाइट को वन मंडलाधिकारी रोहड़ू शाहनवाज अहमद भट्ट ने लांच किया है। इस वेबसाइट में सोसायटी के किसानों की ओर से पैदा होने वाले प्राकृतिक उत्पाद औषधीय विशेषताओं के साथ मिल सकेंगे। इन औषधीय गुणों को औषधीय पौधों के शोधकर्ता राजन रोल्टा एवं उपमंडलीय आयुर्वेदिक स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. दलीप सिंह ने प्रमाणित किया है।

कृपाल सिंह कहते हैं कि लगभग दो दशक से उनके क्षेत्र में लोग प्राकृतिक जड़ी-बूटियों की खेती कर रहे हैं और यहां पैदा होने वाले हर्बल उत्पादों को वह वन विभाग एवं निजी माध्यमों से बाजार में बेच रहे हैं। अब ऑनलाइन बिक्री शुरू की है। उम्मीद की जा रही है कि ऑनलाइन मार्केटिंग से किसानों को औषधीय उत्पादों को बेचने के लिए ग्लोबल बाजार मिलेगा, जिसके चलते उत्पादों को अच्छी कीमत मिलेगी और किसानों की आर्थिकी मजबूत होगी।

लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया

कृपाल सिंह की बचपन से ही औषधिय पौधों में रुचि रही है। साल 2004 में आयुष मंत्रालय की एक सूचना से उनकी रुचि को एक नई दिशा और उम्मीद मिली। उन्होंने जंगलों से पौधे लाना और उन पर रिसर्च करना शुरू कर दिया। किसान जंगलों से रेंज वाइज जड़ी –बूटियां निकालते थे, जो कच्ची और बिना किसी प्रोटोकॉल से निकाली जाती थीं। कृपाल सिंह सोचते थे कि जब इसी तरह से लोग जड़ी–बूटियां निकालते रहेंगे, तो एक दिन सभी प्रजातियां लुप्त हो जाएंगी। उन्हें लगा कि क्यों न इसको खेती में लाया जाए। वे जंगल से पौधे लाकर या बीज लाकर खेती करने लगे। काफी समय तक ऐसे ही करते रहे। उसके बाद उन्होंने कुठ की खेती शुरू की।

कृपाल सिंह बताते हैं कि साल 2012 में उन्हें नौणी यूनिवर्सिटी में तीन दिन की ट्रेनिंग दी गई, जिसमें किसानों को कुठ और अन्य सुगन्धित पौधों की खेती की जानकारी दी गई। उसके बाद वे किसानों को औषधीय पौधों की खेती के लिए जागरूक करते गए। उन्हें चार दिन देरहादून युनिवर्सिटी में औषधीय कृषिकरण की ट्रेनिंग दी गई। इसके बाद उन्होंने अपने क्षेत्र में किसानों के कुछ समूह बनाकर औषधीय पौधों की खेती करनी शुरू कर दी। इस दौरान वे औषधीय कृषिकरण से संबंधित कई कार्यालयों में पहुंच कर कई विशेषज्ञों से मिले।

क्षेत्रीय सुविधा केंद्र का साथ

कृपाल सिंह कहते हैं कि फील्ड विजिट के दौरान उन्हें औषध पादप बोर्ड के क्षेत्रीय संगमता केंद्र के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर अरूण चंदन से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। संवाद के दौरान उन्होंने अपने कृषि कार्य के बारे में बताया। डॉक्टर अरुण चंदन ने उनका मार्गदर्शन किया और उन्ही के मार्गदर्शन से त्रिदेव औषधीय पौध उत्पादन फार्मर्स सोसायटी रोहल गैर सरकारी संस्था के रूप में पंजीकृत हुई और किसानों को औषधीय कृषिकरण की दिशा मिली।

कृपाल सिंह के साथ संस्था से जुड़े सनी मेहता, राकेश मेहता, अंकिता कुमारी, अंजना देवी और राजन रोल्टा औषधीय कृषिकरण के लिए रात दिन कार्य कर रहे है। यह सोसायटी ने औषधीय खेती करने वाले किसानों के लिए निशुल्क कार्य कर रही है।

पांच सौ किसान कर रहे औषधीय खेती

साल 2017 के बाद से त्रिदेव औषधीय पौध उत्पादन फार्मर्स सोसायटी रोहल किसानों को जागरूक करने के लिए खूब प्रयास कर रही है। डॉक्टर अरूण चंदन के मार्गदर्शन और सहयोग से सोसायटी को अदिति द्वारा कुटकी, आतिश, रबीना चीनी, चौरा, महामेदा, सुगंधबाला और धूप प्रजातियों की सर्टिफिकेशन मिली है। डॉक्टर अरुण चंदन का बतौर गुरू, डॉक्टर और साइंटिस्ट इस सोसायटी को इस मुकाम तक पहुंचाने और सफल बनाने में सहयोग मिला है। कृपाल सिंह का कहना है कि हर कार्य को करने में उनका मार्ग दर्शन मिल रहा है। त्रिदेव औषधीय पौध उत्पादन फार्मर्स सोसायटी रोहल से 500 किसान जुड़े हैं। 300 किसानों को जड़ी- बूटियों की खेती के लिए आयुष विभाग द्वारा सब्सिडी दी गई है। त्रिदेव औषधीय पौध उत्पादन फार्मर्स सोसायटी रोहल से किसानों की औषधिय पौधों की खेती से अच्छी आय हो रही है। कुठ, महामेदा आतिश और कुटकी उत्पादन साल दर साल बढ़ रहा है। यह सोसायटी हिमाचल सरकार द्वारा संचालित की जा रही वन समृद्धि-जन समृद्धि योजना के तहत भी औषधीय कृषिकरण को लेकर काम कर रही है।

औषधीय कृषिकरण को मनरेगा का उपहार मिला स्थाई आजीविका और टिकाऊ रोजगार

आरसीएफसी नेटवर्क/हिमाचल

हिमाचल प्रदेश भारत के उन गिने-चुने, राज्यों में शामिल है जहां औषधीय पौधों की खेती को मनरेगा में शामिल करने की अनूठी और सराहनीय पहल हुई है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि हिमाचल प्रदेश के किसान पारंपरिक खेती की जगह औषधीय पौधों की व्यवसायिक खेती के लिए आगे आए हैं। 'मिशन धनवंतरी' के तहत पायलट परियोजना के तौर पर औषधीय कृषिकरण को मनरेगा में शामिल करने की अनूठी पहल साल 2022 में कांगड़ा जिला से हुई थी।

इसके सार्थक परिणामों को देखते 3 अक्तूबर 2024 को हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों में औषधीय कृषिकरण को मनरेगा में शामिल कर लिया गया, जिसके चलते प्रदेश में औषधीय कृषिकरण के लिए वातावरण निर्मित हुआ है। प्रदेश के हजारों किसान और सैंकड़ों स्वंय सहायता समूह औषधीय पौधों की खेती की ओर अग्रसर हुए हैं और राज्य में औषधीय कृषिकरण जनांदोलन का रूप ले चुका है।

तभी लाभ का सौदा बनेगी औषधीय खेती

ग्रामीण स्तर पर टिकाऊ रोजगार और स्थाई आजीविका के इस नवोदित मॉडल के लिए जमीनी स्तर पर किए जा रहे गंभीर प्रयासों के लिए प्रदेश के आयुष विभाग और ग्रामीण विकास विभाग तथा राष्ट्रीय औषध पादप बोर्ड बधाई के पात्र हैं। 'मिशन धनवंतरी' के चलते प्रदेश के किसान औषधीय पौधों की खेती करने का सफल प्रयोग कर चुके हैं।

औषधीय कृषिकरण की वैल्यू चेन के अगले चरण में उच्च मूल्य वाली जड़ी-बूटियों का कृषिकरण

उनका भंडारण, गुणवत्ता नियंत्रण, प्रसंस्करण, टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन जैसे विषय प्राथमिकता होने चाहिए। यह सब व्यवस्था करना किसान के बस की बात नहीं है। इस चरण में किसानों से ज्यादा विभागों की जिम्मेवारी अधिक है, तभी ये खेती किसानों के लिए लाभ का सौदा बन सकेगी।

जैविक संसाधनों का टिकाऊ और वैज्ञानिक दोहन

हिमाचल प्रदेश में व्यवसायिक औषधीय

कृषिकरण अभी शैशवकाल में है, लेकिन प्रदेश के जंगलों में पैदा होने वाली कई जड़ी-बूटियां बहुत पहले से आयुष के उत्पादों में प्रयोग होती आ रही हैं। हिमाचल प्रदेश के जंगलों में नागछतरी, जंगली लहसुन, काला जीरा, कडू पतीश, शुआन, ठांगी, रतन जोत, चोरा, पवाइन, तिला, सालम पंजा, शिंगुजीरा और सालम मिसरी सहित कई बहुमूल्य जड़ी-बूटियां प्राकृतिक तौर पर पैदा होती हैं, जिनका इस्तेमाल आयुर्वेदिक दवाओं के निर्माण में किया जाता है। बड़े पैमाने पर प्रदेश के जंगलों से जड़ी-बूटियों की कलेक्शन की जाती है।

जैविक संसाधनों के लगातार अवैज्ञानिक दोहन के चलते कई महत्वपूर्ण जड़ी-बूटियां विलुप्त होने की कगार पर हैं। कई जड़ी बूटियां और पेड़-पौधे अतिसंवेदनशील श्रेणी में पहुंच गए और कई असुरक्षित और खतरे के नजदीक हैं। ऐसे में जरूरी है कि 'मिशन धनवंतरी' के तहत औषधीय कृषिकरण के साथ प्रदेश के किसानों को वाइल्ड कलेक्शन के लिए भी प्रशिक्षित किया जाए, ताकि जड़ी-बूटियों का टिकाऊ और वैज्ञानिक दोहन संभव हो और दुर्लभ जड़ी-बूटियों का संरक्षण संभव हो।

किसानों को मिले छत

हिमाचल प्रदेश में 'मिशन धनवंतरी' के तहत किसान संगठन और स्वंय सहायता समूह अलग-अलग छोटे स्तर पर औषधीय कृषिकरण और वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। भंडारण, गुणवत्ता नियंत्रण, प्रसंस्करण, टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन जैसी बुनियादी सुविधाओं के अभाव के चलते उनके तैयार किए उत्पाद मुख्यधारा के औषध बाजार का हिस्सा नहीं बन सकते और छोटे से दायरे तक सीमित हैं।

प्रदेश में पैदा होने वाली दिव्य औषधियों से बने उत्पाद राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय औषध बाजार का हिस्सा बन सकें, इसके लिए जड़ी-बूटियों की खेती कर रहे प्रदेश के किसानों को एक छत के नीचे लाना समय की मांग है। तलवाड़ा की उन्नति सहकारी सभा और कुल्लू की भुट्टिको वीवर्स सहकारी सभा के सफल मॉडल की तर्ज पर इसके लिए सहकारिता एक मंच हो सकता है। इसके लिए उपमंडल, जिला अथवा राज्य स्तर पर किसान संगठनों और स्वंय सहायता समूहों की एपेक्स बॉडीज गठित की जा सकती हैं।

ब्रांड बिल्डिंग और क्वालिटी प्रोडक्टस

एपेक्स बॉडीज के गठन की स्थिति में किसानों को क्वालिटी प्लांटिंग मैटीरियल से लेकर उनके उत्पाद की खरीद के लिए स्थाई व्यवस्था बनेगी। जड़ी-बूटियों के भंडारण, गुणवत्ता नियंत्रण, प्रसंस्करण, टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन जैसी बुनियादी सुविधाओं के प्रबंधन सहित प्रॉडक्शन यूनिट स्थापित कर बड़े स्तर पर उत्पादन किया जा सकता है। कच्चे माल की आसान उपलब्धता के चलते एक बड़े ब्रांड के तौर पर क्वालिटी प्रोडक्टस लॉंच कर बड़ी कारोबारी संभावनाएं तलाशी जा सकती हैं।

भारत सरकार देश की 10 हजार फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनियों को कृषि आधारित व्यापार के लिए प्रशिक्षित कर रही है। ऐसी हर फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी को क्रेडिट गारंटी स्कीम के अंतर्गत 5 करोड़ के कोलेट्रल फ्री लोन की सुविधा होगी। केंद्र सरकार की इस योजना का हिस्सा बन उद्यम के लिए वित्त प्रबंधन किया जा सकता है। प्रॉडक्शन यूनिट स्थापित के लिए प्रदेश सरकार जमीन उपलब्ध करवाकर इस मॉडल को मजबूत कर सकती है।

मिशन बन गई एक छोटी सी पहल

राज्य औषध पादप बोर्ड के जिला नोडल अधिकारी डॉ. सुनील शर्मा बताते हैं कि औषधीय कृषिकरण के लिए 'मिशन धनवंतरी' की शुरुआत साल 2022 में कांगड़ा जिला में पांच सौ तैतालीस गांवों की एक सौ बीस पंचायतों में लगभग दो सौ एकड़ भूमि से हुई थी। इसमें जिला के एक हजार तीन सौ चवालिस किसान शामिल हुए और एक सौ बारह स्वयं सहायता समूहों की चार सौ पचास महिलाओं ने भागीदारी की। मिशन के तहत आयुष और ग्रामीण विकास विभाग के सहयोग से कांगड़ा जिला के प्रत्येक ब्लॉक में औषधीय पौधों की नर्सरियां स्थापित की गईं। तुलसी, लेमन ग्रास, काल मेघ, सर्पगंधा आदि औषधीय पौधों का पौधरोपण किया गया।

ब्लॉक से स्टेट लेबल तक 'मिशन धनवंतरी'

'मिशन धनवंतरी' आयुष विभाग के निदेशक डॉ. निपुण जिंदल का ब्रेन चाइल्ड है। कांगड़ा जिला के उपायुक्त रहते हुए उन्होंने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में तुलसी की खेती के साथ एक ब्लॉक से इस मिशन की शुरुआत की थी। उसके बाद कांगड़ा जिला के सभी 20 विकास खंडों में इसका विस्तार किया गया। उनके नेतृत्व में जिला प्रशासन ने विभिन्न स्वंय सहायता समूहों को औषधीय खेती के लिए प्रोत्साहित किया। औषध पादप बोर्ड के क्षेत्रीय सुगमता केंद्र की तरफ से उनको क्वालिटी प्लांटिंग मैटीरियल उपलब्ध करवाया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वंय सहायता समूहों को मिलने वाले स्टार्टअप फंड और रिवॉल्विंग फंड से यह छोटी मशीनरी स्थापित कर जड़ी-बूटियों की उपज की वैल्यू एडिशन कर फाइनल प्रोडक्ट्स बना कर छोटे स्तर पर मार्केटिंग के भी सफल प्रयोग किए गए।

अभिनव प्रयास, किसानों को आस

डॉक्टर निपुण जिंदल जब आयुष विभाग के निदेशक बने तो 'मिशन धनवंतरी' को नई उड़ान मिली। इस मिशन के तहत प्रदेश के सभी जिलों में जड़ी-बूटियों की खेती को मानरेगा में शामिल किया गया। जड़ी-बूटियों की खेती को मनरेगा में शामिल करने के लिए ग्रामीण विकास के निदेशक राघव शर्मा ने गाइडलाइन तैयार कर नया आइडिया पेश किया। इस मिशन के लिए किसानों को नर्सरी और कृषिकरण के लिए क्वालिटी प्लांटिंग मैटीरियल उपलब्ध करवाने वाले औषध पादप बोर्ड के क्षेत्रीय सुविधा केंद्र जोगिन्द्रनगर के क्षेत्रीय निदेशक डॉ. अरुण चंदन कहते हैं कि औषधीय कृषिकरण को मनरेगा में शामिल करना अपनी तरह का अभिनव प्रयास है। औषधीय कृषिकरण की इस पहल को राष्ट्रव्यापी बना कर कृषि आर्थिकी को मजबूत किया जा सकता है। इसके लिए औषधीय कृषिकरण की वैल्यू चेन के हर चरण में गंभीर प्रयासों की जरूरत है।

धरती मां का ऋण चुकाओ, वृक्ष लगाओ, ऑक्सीजन बढ़ाओ

आरसीएफसी नेटवर्क/हरियाणा

कोविड महामारी में पहली बार जब देशभर से ऑक्सीजन की कमी की खबरें आने लगीं, तभी श्रीचंद सुनेजा ने प्रण कर लिया कि 'धरती मां का ऋण चुकाओ, वृक्ष, लगाओ ऑक्सीजन बढ़ाओ।' इस महामारी के प्रकोप के बाद श्रीचंद सुनेजा औषध पादप बोर्ड के क्षेत्रीय सुविधा केंद्र जोगिन्द्रनगर के क्षेत्रीय निदेशक डॉ. अरुण चंदन के संपर्क में आए। उनसे मिलने के बाद वे औषधीय पौधों की तरफ आकर्षित हुए और पौधरोपण को जीवन का लक्ष्य बना लिया।

श्रीचंद सुनेजा के क्षेत्रीय सुविधा केंद्र से जुड़ने के बाद जेबीएम के कई प्लांट्स हर्बल गार्डन वाले कैंपस बन गए। राजधानी दिल्ली और उसके आस-पास अश्वगंधा तथा मोरिंगा जैसे औषधीय पौधे लगाने के लिए बीज और क्वालिटी प्लांटिंग मैटीरियल क्षेत्रीय सुविधा केंद्र की ओर से उपलब्ध करवाया गया। उसके बाद मोरिंगा के प्रचार- प्रसार और उसके कृषिकरण का सिलसिला चल निकला।

कोविडकाल में पौधरोपण की पहल

कोविड के समय श्रीचंद सुनेजा गुजरात में अहमदाबाद के पास सानंद और विट्ठलापुर स्थित कंपनी के प्लांट में कार्यरत थे। यह एक बड़ी मुश्किल स्थिति थी। इसी दौरान उनका गांव के किसानों से जुड़ाव हुआ। उस समय ऑक्सीजन क ी

कमी के चलते लोगों को परेशानी हो रही थी। उन्हें लगा कि ऑक्सीजन बढ़ने से ही सबको लाभ मिलेगा।

श्रीचंद सुनेजा को पौधों से तो पहले से ही प्यार था। कोविड काल में 'धरती मां का ऋण चुकाओ, वृक्ष लगाओ, ऑक्सीजन बढ़ाओ' के साथ वे पौधरोपण के लिए पूरी तरह से समर्पित हो गए। उन्होंने वन विभाग से मिल कर बड़े स्तर पर पौधरोपण शुरू किया और हजारों पेड़ लगाए। उनकी इस मुहिम में सैंकड़ों किसान शामिल हो गए और बड़े पैमाने पर पेड़ लगाने का जन आंदोलन शुरू हो गया।

ओरंगाबाद में तैयार किया जा रहा क्वालिटी प्लांटिंग मैटीरियल

क्षेत्रीय सुविधा केंद्र जोगिन्द्रनगर की टेक्निकल गाइडेंस में हरियाणा के पलवल शहर से आए ओरंगाबाद में बड़े स्तर पर अश्वगंधा और मोरिंगा का क्वालिटी प्लांटिंग मैटीरियल तैयार किया जा रहा है। नर्सरी में ओर भी कई तरह के औषधीय पौधों का क्वालिटी प्लांटिंग मैटीरियल तैयार किया जा रहा है। इसी प्रकार से एनसीआर फरीदाबाद में श्रीचंद सुनेजा लग्न और उत्साह के साथ औषधीय पौधे तुलसी, मोरिंगा, शतवार, सर्पगंधा, अश्वगंधा, अपराजिता और गिलोये आधी की पौध तैयार कर रहे हैं।

इन औषधीय पौधों को बरसात के मौसम में पार्कों में रोपा जाएगा और व्यक्तिगत तौर पर इच्छुक व्यक्तियों को निशुल्क पौधे बांटे जाएंगे।

मोरिंगा की पौध विशेष रूप से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अभियान 'घर-घर तिरंगा, घर- घर मोरिंगा' के मद्देनजर तैयार की जा रही है, जिससे लोग अधिक से अधिक स्वास्थ्य लाभ ले सकें।

मेट्रो सिटीज में मेडिसनल प्लांटस की मुहिम

औषध पादप बोर्ड के क्षेत्रीय सुविधा केंद्र जोगिन्द्रनगर के क्षेत्रीय निदेशक डॉ. अरूण चंदन कहते हैं कि श्रीचंद सुनेजा राजधानी क्षेत्र में औषधीय कृषिकरण के राजदूत के तौर पर भूमिका अदा कर रहे हैं। शहरी क्षेत्रों में औषधीय पौधों को लेकर उनके जन जागरण के शानदार नतीजे सामने आ रहें हैं। उनके प्रयासों से मोरिंगा अभियान के बल मिल रहा है। श्रीचंद सुनेजा बड़े स्तर पर औषधीय पौधों की नर्सरी तैयार कर रहें हैं। वे औषध पादप बोर्ड की ओर से आयोजित होने वाली कार्यशालाओं में भाग लेकर औषधीय कृषिकरण के लिए जरूरी जानकारी जुटाते हैं।

डॉ. अरूण चंदन कहते हैं कि क्षेत्रीय एवं सुगमता केंद्र श्रीचंद सुनेजा को उच्च गुणवत्ता वाला क्वालिटी प्लांटिंग मैटीरियल उपलब्ध करवा रहा है।

हिमाचल की पहली सहकारी औषधीय नर्सरी बन रही है क्वालिटी प्लांटिंग मैटीरियल की उम्मीद

आरसीएफसी नेटवर्क/हिमाचल

हिमाचल प्रदेश के जुब्बड़हट्टी, शिमला में स्थापित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल नर्सरी अब उत्तर भारत के औषधीय कृषकों के लिए गुणवता युक्त रोपण सामग्री (Quality Planting Material) का एक प्रमुख स्त्रोत बन चुकी है। यह राज्य की पहली सहकारी क्षेत्र की हाईटेक औषधीय पौध नर्सरी है, जहां अश्वगंधा, तुलसी, मोरिंगा और अन्य जड़ी-बूटियों के लाखों पौधे तैयार किए जा रहे हैं।

नर्सरी का नवाचार और आधुनिक ढांचा

इस नर्सरी को रामगोपाल ठाकुर और उनके पुत्र जगनमोहन ठाकुर द्वारा संचालित किया जा रहा है। यह एक प्रोटेक्टेड हाउस प्रणाली आधारित नर्सरी है, जिसमें अत्याधुनिक तकनीकों जैसे ऑटोमैटिक सीडिंग मशीन (200 बीज/मिनट), जर्मिनेशन टैंक, और वातावरणीय नियंत्रण यंत्र उपलब्ध हैं।

आरसीएफसी की भूमिका और ट्रायल की सफलता

वर्ष 2024 में क्षेत्रीय एवं सुगमता केंद्र उत्तर भारत-1 (RCFCNR-1), जोगिंदरनगर के सहयोग से इस नर्सरी को उच्च गुणवत्ता वाले औषधीय बीज प्रदान किए गए। ट्रायल सफल

एक आंदोलन की शुरुआत- महाकाली कोऑपरेटिव सोसाइटी

इस सफलता की नींव रखी महाकाली सहकारी समिति ने, जिसने पहले फूलों व सब्जियों की खेती के लिए संघर्ष करते हुए पौध लाने की कठिनाई को पहचाना और स्थानीय नर्सरी की मांग उठाई। रामगोपाल ठाकुर ने इस मुद्दे को तत्कालीन वित्त सचिव श्रीकांत बाल्दी के समक्ष रखा, जिससे राज्य में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस नर्सरी योजना को बजट में स्थान मिला। यह योजना 90% अनुदान और 10% किसान निवेश मॉडल पर आधारित है।

रहे, जिससे यह नर्सरी अब व्यवसायिक स्तर पर जड़ी-बूटी रोपण सामग्री उत्पादन में अग्रसर हो चुकी है। वर्तमान में यहां 10 लाख से अधिक पौधे तैयार हैं, जिनमें औषधीय, फूल और सब्जी श्रेणियां शामिल हैं।

शिमला मिर्च से औषधीय पौध तक

यह नर्सरी हर सीजन में शिमला मिर्च की एक लाख से अधिक पौध उपलब्ध करवाती है और अब सोलन, सिरमौर और अन्य जिलों के किसान भी इससे लाभान्वित हो रहे हैं। रामगोपाल ठाकुर परंपरागत बीजों के संरक्षण की दिशा में भी कार्यरत हैं, और उन्होंने एक सीड बैंक भी स्थापित किया है।

जंगली जानवरों से समाधान की ओर - नवाचार की ओर बढ़ते कदम

रामगोपाल ठाकुर ने अपनी पत्नी, पूर्व सरपंच मीना ठाकुर के सुझाव पर जंगली जानवरों से सुरक्षित फसलें चुनने का निर्णय लिया। फूलों की खेती के लिए उन्होंने पहले मशोबरा, शिमला के डीसी के कार्यक्रम में भाग लिया और प्रशिक्षण हेतु किसानों को NHM सेंटर, तालेगांव, पुणे भेजा।

दस करोड़ का कारोबार और सामुदायिक विस्तार

साल 2009 में महाकाली कोऑपरेटिव सोसाइटी का गठन हुआ। आज इसमें 22 शेयर होल्डर और 100 से अधिक सक्रिय सदस्य हैं। इस सोसाइटी के तहत 5 पंचायतों में खेती हो रही है और अब तक 10 करोड़ से अधिक का कारोबार किया जा चुका है।

नीतिगत प्रोत्साहन और पॉलीहाउस योजनाएं

रामगोपाल ठाकुर बताते हैं कि पहले ग्रीनहाउस निर्माण में 80% किसान निवेश करना होता था, जिससे कई किसान पीछे हट जाते थे। वर्ष 2012 में शुरू हुई पंडित दीनदयाल उपाध्याय पॉलीहाउस योजना ने इस स्थिति को बदल दिया, जिसमें किसान हिस्सेदारी घटाकर 2 लाख कर दी गई। इसी से प्रेरित होकर कई पुराने किसान दोबारा जुड़ गए और सब्जी उत्पादन में सक्रिय हुए।

सहकारिता, नवाचार और आयुर्वेदिक भविष्य का संगम

शिमला की यह सहकारी नर्सरी न केवल हिमाचल प्रदेश की जरूरतों को पूरा कर रही है, बल्कि पूरे उत्तर भारत के लिए एक मॉडल के रूप में उभर रही है। इस नर्सरी ने साबित कर दिया कि यदि नीति, तकनीक और समुदाय का समन्वय हो, तो जड़ी-बूटियों की खेती आत्मनिर्भर भारत की रीढ़ बन सकती है।

चंबा की जंगली जड़ी-बूटियों से बने विशेष उत्पाद शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली की मजबूती की बुनियाद

आरसीएफसी नेटवर्क/हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश में पीर पंजाल और धौलाधार पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बसे चंबा जिला में हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर की सीमा पर स्थित दूरदराज भांदल क्षेत्र में स्थापित 'होलिस्टिक हिमालय' फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी शक्तिशाली एंटी-एजिंग एजेंट बनाने वाली एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर विशिष्ट जड़ी-बूटियों से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने वाले प्री-बायोटिक, प्रो-बायोटिक और पोस्ट-बायोटिक तैयार कर रही है। ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, उनके साथ मिलकर इस फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी का गठन किया गया है।

उत्पाद निर्माण के दौरान शुद्धता और प्रभावकारिता सुनिश्चित करने के लिए कड़े सुरक्षा मानकों का पालन किया जाता है। एफएसएसएई और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद दोनों ने 460 जड़ी-बूटियों की एक सूची को मंजूरी दी है, जिन्हें दैनिक उपभोग के लिए सुरक्षित माना गया है। इन्हीं जड़ी-बूटियों की सूची में शामिल कुछ विशिष्ट जड़ी-बूटियों का प्रयोग कर 'होलिस्टिक हिमालय' अपने उत्पाद तैयार करती है। कंपनी खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएई) से पंजीकृत हैं।

सामाजिक उद्यम जिससे जुड़ी हैं हजारों ग्रामीण महिलाएं

'होलिस्टिक हिमालय' फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी महिला आधारित सामाजिक उद्यम है, जिससे क्षेत्र की हजारों ग्रामीण महिलाएं जुड़ी हैं। कंपनी के अधिकांश शेयर क्षेत्र की महिलाओं के पास हैं। कंपनी के 442 शेयरधारकों में से केवल दो पुरुष हैं। कंपनी के शेयरधारकों के अलावा क्षेत्र की लगभग तीन हजार महिलाएं इस कंपनी के लिए ट्रांस-हिमालयी जड़ी-बूटियों को इकट्ठा करने में भाग लेती हैं। कंपनी के प्रोसेसिंग यूनिट में इन जड़ी-बूटियों का वैल्यू एडिशन कर शरीर की प्रतिरक्षा मजबूत करने वाले प्रोडक्टस बनाए जाते हैं।

चंबा जिला का यह क्षेत्र एक दुर्लभ जैव विविधता वाला हॉटस्पॉट है, जो अद्वितीय प्राकृतिक खजानों से भरा हुआ है। 'होलिस्टिक हिमालय' के उत्पादों के लिए जड़ी-बूटियां सीधे जंगलों और पहाड़ों के प्राचीन वातावरण से प्राप्त की जाती हैं। इन जड़ी-बूटियों को इकट्ठा करने के लिए महिलाएं जंगलों और पहाड़ों में जाती हैं। इस ग्रामीण क्षेत्र की हजारों महिलाओं के लिए जड़ी-बूटियों की कलेक्शन आजीविका का एक महत्वपूर्ण साधन है। फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी से जुड़ी महिलाएं मधुमक्खी पालन, मशरूम की खेती, फूलों की खेती और जैविक खेती भी कर रही हैं।

क्षेत्रीय सुगमता केंद्र का सहयोग

'होलिस्टिक हिमालय' फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी के गठन से लेकर जंगल और पहाड़ पर जड़ी- बूटियों की पहचान करने, तथा उनके टिकाऊ और वैज्ञानिक दोहन के लिए महिलाओं को प्रशिक्षित करने में क्षेत्रीय सुगमता केंद्र जोगिन्द्रनगर का भरपूर तकनीकी सहयोग रहा है। हिमाचल प्रदेश सीएम स्टार्टअप प्रोजेक्ट में शामिल इस 'होलिस्टिक हिमालय' के स्टार्टअप आइडिया को बिजनेस आइडिया में बदलने में क्षेत्रीय सुगमता केंद्र ने इंकूबेशन सेंटर के तौर पर मदद की है। क्षेत्रीय सुगमता केंद्र ने इस फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी को जड़ी-बूटियों से फाइनल प्रॉडक्ट विकसित करने में टेक्निकल स्पोर्ट दी है।

क्षेत्रीय सुगमता केंद्र जोगिन्द्रनगर उत्तर भारत के विभिन्न स्थानों पर होने वाले कार्यक्रमों में 'होलिस्टिक हिमालय' के प्रोडक्टस को प्रदर्शित करने के लिए स्टाल और इन प्रोडक्टस की विशेषताएं लोगों को बताने के लिए मंच प्रदान कर इन उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने में सहयोग कर रहा है। यही वजह है कि 'होलिस्टिक हिमालय' के उत्पादों के लिए प्रॉडक्शन से ज्यादा डिमांड आनी शुरू हो गई है।

शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य का मॉडल

'होलिस्टिक हिमालय' फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी के सीईओ एवं निदेशक डॉ. मोहम्मद रियाज एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, जिन्हें शरीर विज्ञान और उपचार की गहन समझ है। उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ से अकादमिक शोध और स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग में रोग उपचार में व्यावहारिक अनुभव हासिल किया है। उन्होंने आयुष मंत्रालय के अधीन संचालित औषध पादप बोर्ड के क्षेत्रीय सुगमता केंद्र जोगिन्द्रनगर से स्वदेशी औषधीय पौधों से उत्पाद विकसित करने में विशेषज्ञता हासिल की है।

'होलिस्टिक हिमालय' शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक हेल्थ पर केंद्रित है। डॉक्टर रियाज बताते हैं कि उनका प्राथमिक फोकस समग्र स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले आंत के उपचार पर है, जिसे दूसरा मस्तिष्क कहा जाता है। आंत के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए व्यक्ति की दिनचर्या में प्री-बायोटिक्स, प्रो-बायोटिक्स और पोस्ट-बायोटिक्स को शामिल करना आवश्यक है।

'होलिस्टिक हिमालय' शारीरिक स्वास्थ्य की देखभाल के लिए हर्बल समाधान और मानसिक स्वास्थ्य के लिए अरोमाथेरेपी तेल, प्लेसीबो थेरेपी, हाइड्रोपैथी, मिट्टी स्नान और एक्यूप्रेशर उपचार प्रदान करती है। कई नामी दवा कंपनियां 'होलिस्टिक हिमालय' के उत्पादों की ग्राहक हैं। डॉक्टर रियाज कहते हैं कि भारत में 3,500 से अधिक औषधीय पौधे हैं। देश के प्रत्येक क्षेत्र में कई विशिष्ट औषधीय पौधे हैं, जो विभिन्न बीमारियों का इलाज करने में सक्षम हैं।

किसी भी विशिष्ट जड़ी-बूटी से आधार यौगिकों को निकालकर उनसे भोजन, सौंदर्य प्रसाधन और दवाओं के रूप में काम करने वाले बहुमुखी उत्पाद बनाए जा सकते हैं। डॉ. मोहम्मद रियाज कहते हैं कि 'होलिस्टिक हिमालय' लोगों को इन विशिष्ट जड़ी-बूटियों को मूल्य-वर्धित उत्पादों में बदलने के तरीकों के बारे में शिक्षित करने के लिए समर्पित है।

पलवल के दो सगे भाई बने प्रगतिशील किसान हरियाणा में औषधीय खेती चढ़ने लगी परवान

हरियाणा सरकार ने बजट में किया प्रावधान

आरसीएफसी नेटवर्क/हरियाणा

हरियाणा सरकार ने 2025 के अपने वार्षिक बजट में पहली बार औषधीय कृषिकरण के लिए अलग से बजटीय प्रावधान किया है। राज्य सरकार ने आयुष की दिशा में यह बड़ा कदम पलवल जिला के ओरंगाबाद गांव के दो भाईयों इंजीनियर दीपेश चौहान और फार्मासिस्ट राकेश चौहान के सुझावों पर उठाया है। औषधीय कृषिकरण की वकालत करते हुए इन चौहान बंधुओं ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को लिखे पत्र में कहा था कि जड़ी-बूटियों की खेती से जहां राज्य में प्राकृतिक खेती की मुहिम को बढ़ावा मिलेगा, वहीं किसानों की आय में भी बढ़ोतरी होगी।

उन्होंने औषधीय कृषिकरण के ग्रामीण स्तर पर स्थापित अपने सफल मॉडल का भी हवाला दिया था। औषधीय पौधों की खेती, प्रोसेसिंग तथा वैद्य रहे दादा से विरासत में मिले परंपरागत उपचार के ज्ञान से वैल्यू एडिशन कर औषधीय खेती के सफल किसान बने चौहान बंधुओं ने अब अपनी पंचायत को हर्बल पंचायत बनाने का बीड़ा उठाया है। राज्य सरकार के नीति निर्धारण में दखल देकर हरियाणा में औषधीय कृषिकरण के रोल मॉडल बने चौहान बंधुओं की संघर्ष से सफलता की यह यात्रा रोचक, मनोरंजक और ज्ञानवर्धक है।

मां की बीमारी ने बदला खेती का तरीका

साल 2016 में चौहान बंधुओं की माता को दिल के रोग ने घेर लिया। सर्जरी हुई तो पता चला कि लगातार दर्दनिरोधक दवाइयों के सेवन, रासायनिक खादों से तैयार आनाज और सब्जियों का प्रयोग करने से कारण उनकी मां दिल की बीमारी की चपेट में आई थी। इस जानकारी के मिलते ही मूल रूप से कृषक, पशुपालक तथा स्थानीय जड़ी-बूटियों और उनके सेवन की समझ रखने वाले चौहान परिवार ने खेती को बदलने का फैसला किया।

चौहान बंधुओं ने ओर्गेनिक खेती की तरफ कदम बढ़ाए। दस एकड़ में ओर्गेनिक तरीके से गेंहू की खेती की। खेती के लिए जुनून तो बहुत था, लेकिन इस दिशा में जानकारी के अभाव के चलते प्रति एकड़ बहुत ही कम पैदावार हुई और तगड़ा घाटा सहना पड़ा। वे रासायनिक खेती के खतरे को भांप चुके थे और ओर्गेनिक खेती करके नुकसान झेल चुके थे।

प्राकृतिक खेती के मास्टर ट्रेनर्स

इस बीच चौहान बंधुओं को प्राकृतिक खेती के बारे में पता चला तो वे कुरुक्षेत्र के गुरुकुल में पहुंच गए, जहां आचार्य देवव्रत किसानों को प्राकृतिक खेती के गुर सीखा रहे थे। उन्होंने गुरुकुल से प्राकृतिक खेती करने का प्रशिक्षण लिया। वे जिला में प्राकृतिक खेती के मास्टर ट्रेनर बनाए गए। अब प्राकृतिक खेती उनके जीवन का मिशन बन गया।

चौहान बंधु अब खुद तो प्रकृतिक खेती कर ही रहे हैं, वे जिला के एक हजार से ज्यादा किसानों को भी प्राकृतिक खेती करने की दिशा में मोड़ चुके हैं। जहरमुक्त खेती के लिए उनके प्रयासों के लिए कई मंचों पर उनका सार्वजनिक अभिनंदन किया गया है।

चुनौतियों भरे सफर में कई नाकामियां भी शामिल

फार्मासिस्ट राकेश चौहान बताते हैं कि औषधीय कृषिकरण का उनका सफर कई चुनौतियों भरा रहा है और इसमें कई नाकामियां शामिल हैं। उन्होंने कृषि विभाग, बागवानी विभाग और आयुष विभाग, हर संस्थान में पहुंच कर विशेषज्ञों की मदद ली। एक बार ऐसा भी हुआ कि जब उन्होंने एक क्विंटल सफेद मूसली का बीज लगाया और उत्पादन महज दस किलो हुआ।

लोग दोनों भाईयों को पागल और बेवकूफ तक कहने लगे थे और घर पर भी उनके प्रयोगों पर उंगलियां उठने लगी थी। सफेद मूसली उगाने का प्रयोग असफल हुआ, तो उन्होंने ओर्गेनिक गन्ने की खेती में हाथ आजमाए। गन्ने से ओर्गेनिक गुड़ तैयार किया, जिसे अच्छी कीमत मिली और उन्हें खेती में नए प्रयोग करने की नई ताकत मिली।

औषधीय कृषिकरण की नई क्रांति का किया सूत्रपात

इंजीनियर दीपेश चौहान बताते हैं कि उनके दादा लाल पित्ती की दवाई देते थे। वे खेतों में पैदा होने वाली एक जड़ी को गुड़ में मिला कर दवा तैयार करते थे, जो रामबाण थी। वे मोच का भी उपचार करते थे। दादा खेतों की मेड़ों पर लगने वाली जिन जड़ी-बूटियों का प्रयोग करते थे, खरपतवार नाशक रासायनों के चलते पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थीं।

दीपेश कहते हैं कि राष्ट्रीय औषध पादप बोर्ड के क्षेत्रीय एवं सुगमता केंद्र उत्तर भारत -1, जोगिंद्रनगर की ओर से औषधीय पौधों के कृषिकरण, संरक्षण, विकास और विपणन के लिए कुरुक्षेत्र में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्हें जड़ी-बूटियों की खेती की अपार संभावनाओं के बारे में पता चला।

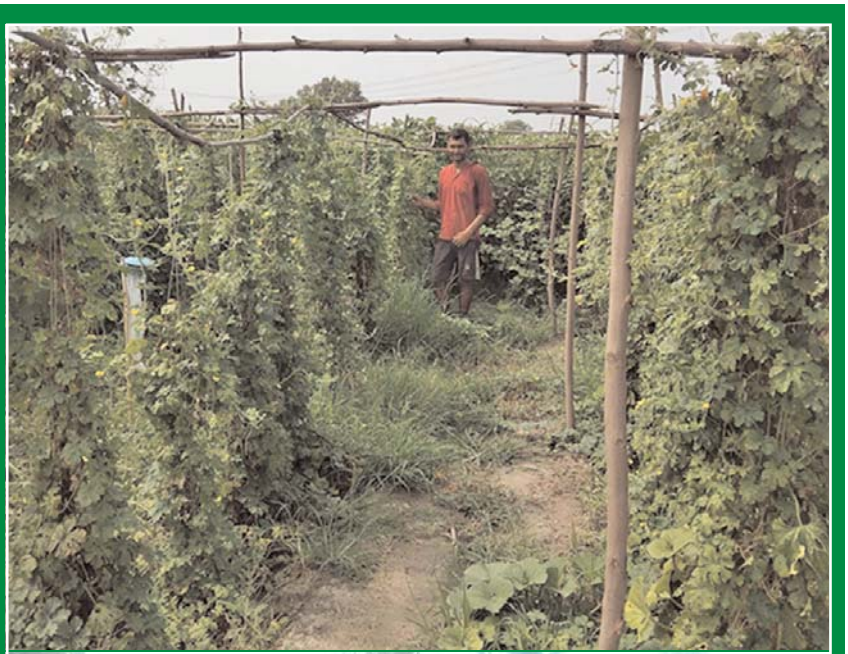

असिस्टेंट कमांडेंट उत्कृष्ट पांडे का 'मातृवंदन' उत्तर प्रदेश की जमीन पर उगा दिया सफेद चंदन

अब सफेद चंदन की खेती करने को आगे आए राज्य के हजारों किसान

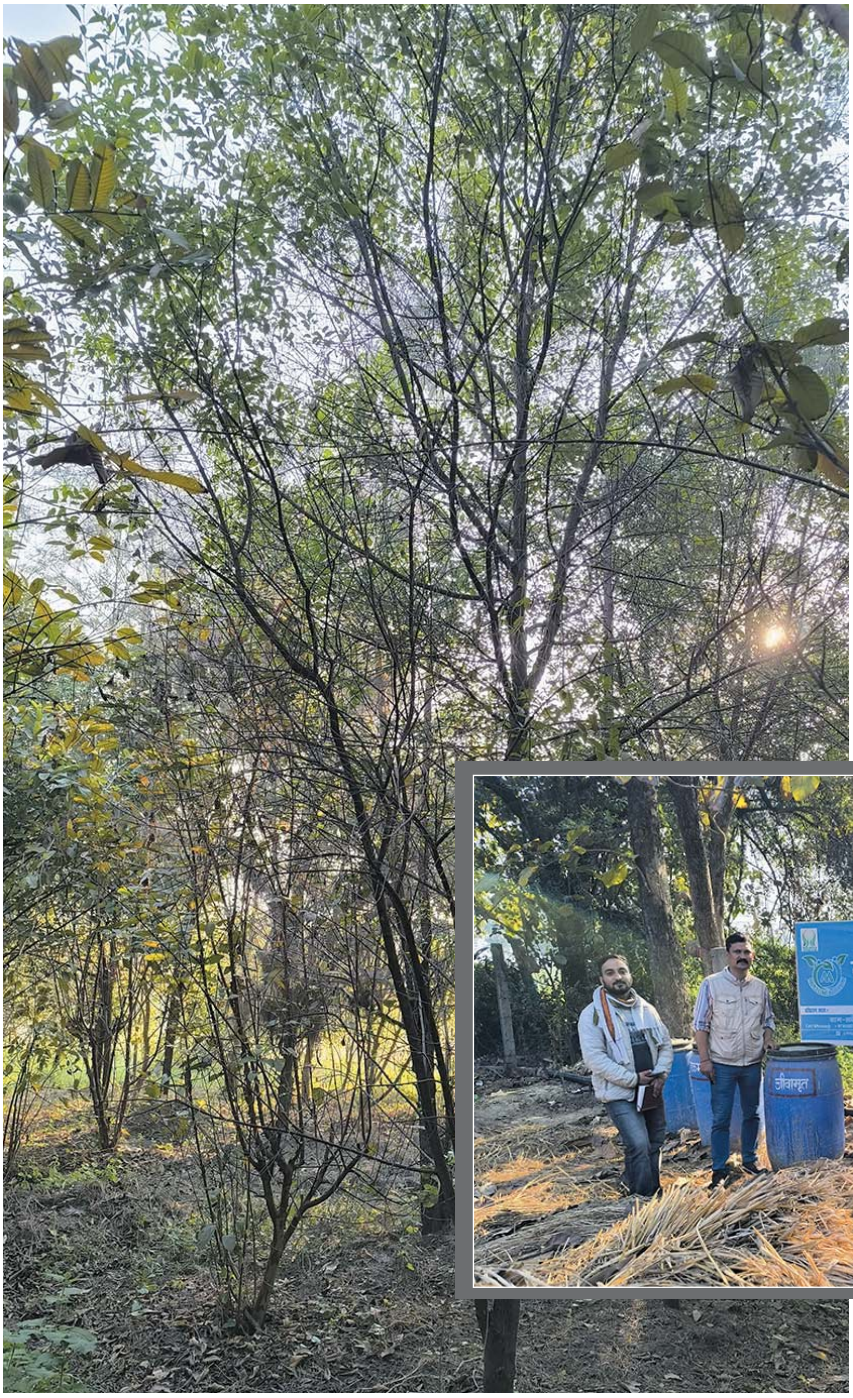

आरसीएफसी नेटवर्क/उत्तर प्रदेश

ज्यादातर लोगों को इतना ही पता है कि चंदन सिर्फ दक्षिण भारत में ही उगाया जा सकता है, लेकिन ताजा सच यह है कि उत्तर भारत भी सफेद चंदन की खेती के लिए अनुकूल है। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में असिसंटेंट कमांडेंट रहे उत्कृष्ट पांडे ने लखनऊ से 200 किलोमीटर दूर प्रतापगढ़ के भदौना गांव में चंदन की खेती और नर्सरी का सफल प्रयोग कर उत्तर प्रदेश के किसानों को नई राह दिखाई है। उत्कृष्ट पांडे के सफेद चंदन की खेती के मिशन से जुड़कर उत्तर प्रदेश के दो दर्जन जिलों के हजारों किसान चंदन की खेती के अग्रदूत बने हैं।

प्रतापगढ़, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, कानपुर, उरई, एटा, जौनपुर, बनारस, भदोही, प्रयागराज, कौशांबी, फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट, झांसी, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, गोरखपुर, गाजीपुर, देवरिया और बदायूं जैसे जिलों के हजारों किसान उनकी नई पहल में शामिल होकर सफेद चंदन की खेती कर रहे हैं।

सफेद चंदन का क्वालिटी प्लांटिंग मैटीरियल

'मर्सिलोना एग्रोफार्म' की नर्सरी में सफेद चंदन का क्वालिटी प्लांटिंग मैटीरियल तैयार कर देश भर के किसानों को उपलब्ध करवाया जा रहा है। मार्सिलोना एग्रोफार्म चंदन की खेती, औषधीय पौधों की खेती और जैविक खेती के लिए किसानों को नि:शुल्क प्रशिक्षण रहा है। देश के कई हिस्सों के लोग प्रशिक्षण और एग्री टूरिज्म के लिए मार्सिलोना एग्रोफार्म में आते हैं। यहां मिट्टी की जांच कर उसके स्वास्थ पर भी काम किया जाता है। भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने मर्सीलोना एग्रोफार्म को प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए अधिकृत किया है। उत्कृष्ट पांडे 4 एकड़ में फैले अपने 'मर्सिलोना एग्रोफार्म' में सफेद चंदन और काली हल्दी की खेती कर किसानों के लिए इंसपिरेशन बन गए हैं। सफेद चंदन की खेती की यह पहल ग्रामीणों का पलायन रोकने में मदद कर रही है। यह मुहिम आने वाले दशक में उत्तरी भारत की कृषि आर्थिकी का चेहरा बदल सकती है।

अध्ययन, प्रशिक्षण, फिर कृषिकरण

सफेद चंदन की खेती करने के लिए गहन अध्ययन के बाद उत्कृष्ट पांडे ने चंदन पर रिसर्च करने वाले बेंगलुरु स्थित देश के सबसे बड़े इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी से चंदन के कृषिकरण, प्रेसेसिंग और वेल्यू एडिशन की ट्रेनिंग ली। उन्होंने कई कृषि विश्वविद्यालयों, कृषि विशेषज्ञों और किसानों के पास जाकर जैविक खेती और प्राकृतिक खेती के गुर भी सीखे। उन्होंने औषधीय खेती और प्रोसेसिंग का भी प्रशिक्षण हासिल किया है।

उत्कृष्ट पांडे बताते हैं कि चंदन की भी कई किस्में होती है, लेकिन भारत में प्रमुख तौर पर सफेद और लाल चंदन ही उगाया जाता है। वे बताते हैं कि सफेद चंदन की खेती के लिए उत्तर प्रदेश का वातावरण अनुकूल है। यहां छिटपुट रूप से चंदन होता रहा है, जिसका वर्णन साहित्य में मिलता है। चंदन का पौधा किसी भी मौसम में लगा सकते हैं। इसको बहुत ज्यादा देखभाल की जरूरत नहीं पड़ती। खेत की मेड़ पर चंदन के पौधे लगाए जा सकते हैं। इसे कम पानी की जरूरत होती है। यह पौधा कृषि वानिकी के लिए अनुकूल पौधा है। अब एक मुहिम के रूप में उत्तर प्रदेश में चंदन की खेती की शुरुआत हुई है।

चंदन का अर्थशास्त्र : 15 साल बाद 2 करोड़ की कमाई

दुनिया भर में सफेद चंदन की काफी ज्यादा डिमांड है। इसका इस्तेमाल परफ्यूम बनाने में किया जाता है। चंदन के कई औषधीय गुण होते हैं, जिसकी वजह से सफेद चंदन काफी महंगा बिकता है। तमिलनाडु और कर्नाटक सफेद चंदन के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में सफेद चंदन की खेती अभी शैशवकाल में है और रोपाई के दौर से गुजर रही है। एक दशक बाद इसके नतीजे सामने आएंगे।

उत्कृष्ट पांडे सफेद चंदन का अर्थशास्त्र बताते हुए कहते हैं कि एक किसान करीब 250 पेड़ लगाकर 14 से 15 साल बाद 2 करोड़ से ज्यादा पैसा कमा सकता है। वे कहते हैं कि क्वालिटी के आधार पर काली हल्दी भी 1,000 रुपए प्रति किलोग्राम तक बिकती हैं। बाजार में इन दोनों की भारी डिमांड रहती है। सफेद चंदन और काली हल्दी की खेती किसानों की आमदनी बढ़ाने में भी मदद करती है।

भारी मांग, शानदार कीमत

उत्कृष्ट पांडे के अनुसार सफेद चंदन में लगभग 6 वर्ष बाद से हर्टवुड बनाने लगती है, जो चंदन में सुगंध का कारण होती है। चंदन का पौधा 100 रुपए से 150 रुपए तक में मिल जाता है। एक एकड़ में 250 से 300 पौधे लगाए जा सकते हैं।

पांडे कहते हैं कि चंदन का उत्पादन आपूर्ति के मुकाबले काफी कम है, इसलिए चंदन की तस्करी होती है। कन्नौज में इत्र का काम होता है, जो चंदन के लिए भारत का सबसे बड़ा बाजार है।

चंदन का इस्तेमाल सबसे ज्यादा परफ्यूम में किया जाता है। आयुर्वेद में चंदन का खूब इस्तेमाल किया जाता है। चंदन का तेल भी तैयार किया जाता है। ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। चंदन की लकड़ी 10 हजार से 15 हजार रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिकती है, जबकि चंदन का तेल गुणवता के आधार पर 4-5 लाख रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बिकता है।

कृषि अर्थव्यवस्था के लिए शुभ संकेत

उत्कृष्ट पांडे ने सुरक्षाबल में नौकरी के दौरान बिहार, झारखंड और असम में साढ़े 5 साल तक देशसेवा की। इस दौरान हमेशा वे अपने गांव और गांव में लोगों की मदद के विचार करते रहे। हमारे ग्रामीण युवा देश को आत्मनिर्भर बनाने में मदद कैसे करें, इसी विचार के चलते साढ़े पांच साल देशसेवा करने के बाद उत्कृष्ट पांडे ने साल 2016 में पुश्तैनी खेती को आगे बढ़ाने के लिए अपनी जॉब छोड़ दी।

लगभग एक दशक के अथक प्रयासों के चलते उत्कृष्ट पांडे उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए प्रेरक बन गए हैं। अब वे अपने जैविक और औषधीय उत्पादों के निर्यात की राह बनाने में जुटे हुए हैं। नौकरीपेशा और पेशेवरों का औषधीय खेती की तरफ मुड़ना और इंसपिरेशन बनकर सामने आना देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए शुभ संकेत हैं।

अगर आप सफेद चंदन की खेती करना चाहते हैं तो उत्कृष्ट पांडे का मार्गदर्शन आपके बड़े काम का हो सकता है।
संपर्क – https://marceloneagrofarms.com/ 9580250135

ऊना की बंजर जमीन पर हर्बल खेती की जुबानी महिलाएं लिख रहीं आर्थिक आजादी की कहानी

आरसीएफसी नेटवर्क/हिमाचल प्रदेश

इंडकेयर ट्रस्ट की प्रबंध ट्रस्टी और सामाजिक क्षेत्र में 32 वर्षों का अनुभव रखने वाली रीवा सूद की दूरदर्शी सोच से ऊना जिला की बेहड़ जसवां पंचायत एक दशक से भी कम के कालखंड में औषधीय कृषिकरण के बलबूते महिला सशक्तिकरण और सतत् आजीविका की मौन क्रांति की गवाह बन गई है। इस पंचायत की ग्रामीण महिलाओं को प्राकृतिक खेती, औषधीय कृषिकरण में दक्ष करने और कृषि उपज व मेडिसिनल हर्ब्स के कारोबार की समझ देने के लिए साल 2016 में वुमेन फार्मर्स प्रोड्युसर कंपनी Him2Hum का गठन किया था। वर्तमान में 230 महिलाएं इस वुमेन फार्मर्स प्रोड्युसर कंपनी का हिस्सा हैं, जो ऊना में ऑर्गेनिक खेती के जरिए खेती के पुराने तरीकों और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन तकनीकों में नए बदलाव की गवाह बन रही हैं।

Him2Hum को नेशनल लेवल बैंक फॉर फार्मर्स, रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम और नाबार्ड ने वित्त पोषित किया है। यह वुमेन फार्मर्स प्रोड्युसर कंपनी प्राकृतिक, जैविक और हर्बल उत्पादों का निर्माण करती है। उनके उत्पादों की बाजार में भारी मांग है। स्वाति स्पेनटोज प्राइवेट लिमिटेड, केटाव्स, आयुष स्वास्थ्य देखभाल और बायोस्फीयर क्लिनिकल जैसे बड़े खिलाड़ी उनके उत्पादों के ग्राहक हैं। फार्मर्स प्रोड्युसर कंपनी से जुड़ीं महिला किसान अब ग्लोबल बिजनेस चलाने का हुनर सीख रही हैं।

महिलाएं पढ़ रहीं आर्थिक आजादी का पाठ

रीवा सूद स्थानीय महिलाओं को सशक्त बनाना चाहती थीं। रीवा बताती है, 'जब मैं पहली बार यहां आई थी, तो मैंने देखा कि महिलाएं पशुपालन करती हैं और खेतों में जाती हैं, लेकिन किसी प्रोजेक्ट को औपचारिक रूप से करने के लिए कहा जाता है तो काफी संकोच करती हैं। वह इस संकोच को हटाकर सुनिश्चित करना चाहती थी कि हर महिला के पास अपना पैन कार्ड और हस्ताक्षर करने का अधिकार हो। Him2Hum से जुड़ी सैंकड़ों महिलाओं को आर्थिक आजादी के बारे में सिखाया जाता है व सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूक किया जाता है। महिलाओं का किसान बुक में नाम होना अनिवार्य बनाया जा सके, इसके लिए भी रीवा सूद प्रयासरत हैं।

जैविक खेती से शुरुआत, औषधीय कृषिकरण का साथ

दिल्ली निवासी रीवा सूद के पति राजीव कैंसर की चपेट में आ गए थे। कारण यह सामने आया कि दिल्ली में वे जिन सब्जियों का उपभोग कर रहे हैं, उनमें काफी मात्रा में जहरीले तत्व मौजूद हैं। 2012 में इस दंपति ने दिल्ली छोड़ने का फैसला कर ऊना का रुख किया। रीवा सूद ने बेहड़ जसवां गांव में बंजर पड़ी 30 एकड़ पैतृक जमीन पर जैविक खेती की पहल खीरे से की गई। वे जैविक और औषधीय पौधों की खेती करने वाले ऊना, कांगड़ा और चंबा के कई किसानों से जुड़ीं।

राष्ट्रीय औषध पादप बोर्ड का क्षेत्रीय एवं सुगमता केंद्र उत्तर भारत, जोगिंद्रनगर के प्रयासों से रीवा सूद ने औषधीय कृषिकरण की दिशा पकड़ी और कुछ ही सालों में उनकी जमीन पर शतावरी, सर्पगंधा, अश्वगंधा, तुलसी, स्टीविया, हारसिंगार, एलोवेरा, वीटिव ग्रास और लेमन ग्रास सहित 17 किस्मों की औषधीय फसलें उगाई जाने लगीं।

काले गेहूं और ड्रैगन फ्रूट की खेती

रीवा सूद सुपरफूड माने जाने वाले काले गेहूं और ड्रैगन फ्रूट की खेती भी करती हैं। वे पूरी तरह ऑर्गेनिक खेती करती हैं। जमीन को पोषण देने और उपजाऊ बनाने के लिए गौ मूत्र, गाय का गोबर, पंचगव्य, नीम स्प्रे और लस्सी का इस्तेमाल किया जाता है। ये सभी सामग्रियां स्थानीय रूप से उपलब्ध होती हैं।

रीवा सूद बताती हैं कि अपने जमीन के टुकड़े को पूरी तरह से जैविक खेती और औषधीय खेती के लिए बदलने में उन्हें छह साल का वक्त लगा। कई बार उन्होंने 40 डिग्री तापमान में भी काम किया।

किसानों को साथ लाना एक कठिन काम था। उसके जुनून को देखते हुए 10 किसान उनके साथ आए। प्रयोग सफल रहा तो कई किसान उनके साथ जुड़ते गए।

सड़क पर घूमते पशुओं को बसेरा

रीवा सूद ने बूढ़ी गायों और नर बछड़ों के लिए अपने खेत में ही एक शेड बनाया। ग्रामीणों से ऐसी बूढ़ी गायों को यहां लाने के लिए कहा। शेड में पशु पहुंचे तो रीवा सूद ने वर्मिकम्पोस्ट गड्ढे के लिए उनके गोबर का उपयोग करना शुरू कर दिया। यह एक बड़ा उदाहरण बन गया कि अगर ठीक से इस्तेमाल किया जाए, तो बेकार समझा जाने वाला बुजुर्ग पशुधन भी उपयोगी हो सकता है।

उन्होंने ग्रामीणों को जमीन पर बनाए गए गड्ढे में कचरे के छिल्के, लस्सी आदि फैंकने के लिए प्रोत्साहित किया। इससे जीवामृत बनता है, जो मिट्टी को उपजाऊ बनाने में मदद करता है। समय के साथ गांव वाले भी जैविक और औषधीय खेती से संबन्धित कई चीजें सीख रहे हैं।

कॉर्पोरेट जगत में शानदार पहचान

रीवा सूद तनिष्का नेचुरल्स एग्रो प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की निदेशक हैं। कंपनी हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों से प्राकृतिक उत्पादों को देश के हर घर तक पहुंचाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। कंपनी का कॉर्पोरेट कार्यालय दिल्ली में है, जिसके उत्पादों का देशव्यापी वितरण है।

कंपनी प्रसंस्करण, उपभोग और निर्यात के लिए प्राकृतिक, जैविक और हर्बल उत्पाद बनाती है। रीवा सूद अग्रीवा नेचुरली कंपनी की प्रबंध निदेशक है, जो फ्रूट और वेजीटेबल जूस का उत्पादन करती हैं। जैविक, हर्बल और औषधीय उत्पाद बनाने वाली उनकी कंपनियों की कॉर्पोरेट जगत में शानदार पहचान है।

यू ट्यूब के जरिये यमुनानगर के धर्मवीर से पहचान गोंडा के शिव कुमार मौर्या के लिए बन गई वरदान

आरसीएफसी नेटवर्क/उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश के गोंडा जनपद के शिव कुमार मौर्या की नौकरी छूटी और फिर मनचाही नौकरी नहीं मिली, तो उन्होंने घर लौट कर पुश्तैनी जमीन पर खेती करने का फैसला किया। एक दिन वे जब यूट्यूब पर खेती से संबन्धित वीडियो सर्च कर रहे थे, तो उन्हें मल्टी प्रोसेसिंग मशीन के आविष्कारक यमुनानगर के प्रगतिशील किसान धर्मवीर कंबोज की सक्सेस स्टोरी का वीडियो मिला। वे धर्मवीर कंबोज से मिलने यमुनानगर पहुंच गए और उनसे पहली ही मुलाकात उनके लिए वरदान बन हुई। उनकी सलाह से वे औषधीय कृषिकरण करने वाले राजस्थान के किसानों से मिले। धर्मवीर कंबोज से उन्होंने मल्टी प्रोसेसिंग मशीन और जड़ी-बूटियों को सुखाने के लिए ड्रायर खरीदा। शिव कुमार मौर्या ने औषधीय पौधों की खेती और प्रोसेसिंग शुरू की। उन्होंने एलोवेरा जेल और गुलाब जल बनाया। तुलसी उगाकर उसका अर्क और पंचांग बनाने का काम शुरू किया। पांच साल पहले उन्होंने मोरिंगा की नर्सरी लगाई और खेती शुरू की। अब औषधीय कृषिकरण, सब्जी उत्पादन और फल उत्पादन का उनका यह मॉडल किसानों के लिए प्रेरणा का स्त्रोत बन गया है। वे 10 बार आकाशवाणी लखनऊ और दो बार डीडी किसान चैनल पर अपनी सक्सेस स्टोरी सुनाने का अवसर मिला है।

पिता का अनुभव बेटे के आया काम

शिव कुमार मौर्या के पिता वंशराज मौर्य ने अपनी एक एकड़ जमीन पर 500 से अधिक दुर्लभ प्रजाति के औषधीय लगाए थे। वे बचपन से ही देखते आ रहे थे कि उनके पिता किस मौसम में कौन सा औषधीय पौधा रोपते हैं। उनके पिता को जड़ी-बूटियों से उपचार करने की गहरी समझ थी। उनके घर पर रोज कई लोग दवाई के लिए आते थे। शिव कुमार मौर्या के पिता किसी मरीज को किसी पेड़ का पता तोड़ के देते, किसी को किसी पेड़ की छाल तो किसी को किसी जड़ी का काढ़ा बना कर देते। इससे वे लोग ठीक हो जाते। बचपन में बेशक बेटे को इस बारे में कोई ज्यादा समझ नहीं थी, लेकिन जब वे जड़ी-बूटियों की खेती में उतरे तो पिता के औषधीय पौधों के बारे में अनुभव बेटे के बड़े काम आए।

नौकरी छूटी तो खेती करने का बनाया मन

शिव कुमार मौर्या बताते हैं कि गोंडा जनपद सब्जी उत्पादन को लेकर जाना जाता है। यहां की सब्जियां नेपाल तक बिकती हैं। सब्जी उत्पादन के साथ समस्या यह कि अधिक उत्पादन होने पर मार्किट में दाम कम मिलते हैं और उत्पादकों को घाटा उठाना पड़ता है। सब्जी उत्पादन में जोखिम के चलते उन्होंने नौकरी करने को तरजीह दी। उन्होंने पहले लेबर ब्यूरो में काम किया फिर नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस में इन्वेस्टिगेटर का काम किया।

सब कुछ टीक चल रहा था कि एक दिन अचानक उनकी नौकरी चली गई। फिर से नौकरी हासिल करने के लिए उन्होंने दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे महानगरों सहित कई शहरों के चक्कर काटे, लेकिन पसंद की जॉब नहीं मिली। ऐसे में उनके पास घर लौट कर पुश्तैनी खेती करने का ही विकल्प था। वे घर लौटे तो खेती में नए प्रयोग करने की धुन सवार हुई, जिसके चलते वे प्रगतिशील किसान धर्मवीर कंबोज के संपर्क में आए।

किताब पढ़ कर पहुंच गए राजस्थान

शिव कुमार मौर्या को धर्मवीर कंबोज के घर पर एक पुस्तक मिली, जिसमें औषधीय कृषिकरण कर सफलता का इतिहास बनाने वाले देश भर के 56 किसानों की प्रेरककथाएं छापी गईं थीं। वे एक ही रात में पूरी किताब पढ़ गए। ज्यादातर सफल किसान राजस्थान के थे। राजस्थान के किसानों से मिलने के लिए धर्मवीर कंबोज के कनेक्शन उनके बड़े काम आए।

वे राजस्थान में औषधीय खेती करने वाले राकेश चौधरी से मिले और औषधीय खेती और उसकी प्रोसेसिंग का बारीकी से अध्ययन किया। वे जयपुर और सीकर सहित राजस्थान के कई हिस्सों में जड़ी-बूटियों की खेती करने वाले किसानों से मिले। अब तक वे औषधीय खेती के बारीकियों को समझ चुके थे और उनकी खेती करने के लिए मानसिक तौर पर तैयार हो चुके थे।

'अरगा' ब्रांड, रिलायंस मार्ट में सेल

सबसे पहले शिव कुमार मौर्या ने एलोवेरा की खेती की। धर्मवीर कंबोज से मल्टी प्रोसेसिंग मशीन ड्रायर खरीदने के बाद उन्होंने एलोवेरा को प्रोसेस कर बेचा, जिसकी अच्छी कीमत मिली। उत्साहित होकर गुलाब जल बनाया। सी मैप लखनऊ से तुलसी की सेसेरियम वैरायटी का एक पौधा लाकर आधे एकड़ में तुलसी की खेती की और तुलसी अर्क निकालने लगे। पांच साल पहले उन्होंने मोरिंगा की नर्सरी विकसित की और उसकी खेती करने लगे। इलेक्ट्रिक ड्रायर से मोरिंगा की पत्तियों को सुखाने में मदद मिली।

बाल विकास परियोजना अधिकारी अरुण मोली ने गोंडा जनपद में बनने वाले हर्बल प्रोडक्टस को प्लेटफॉर्म देने के लिए 'अरगा' ब्रांड नाम से मार्केट में उतारा। 'अरगा' ब्रांड के तहत गोंडा जनपद में वर्तमान में 42 प्रकार के हर्बल उत्पाद मार्केट किए जा रहे हैं, जिनमें शिव कुमार मौर्या के मोरिंगा और गन्ने के छिलके के उत्पाद शामिल हैं। ये उत्पाद गोंडा स्थित रिलायंस मार्ट पर बिक रहे हैं।

फार्म पर पहुंच गए उपायुक्त

शिव कुमार मौर्या ऑनलाइन और ऑफलाइन मार्केटिंग करते हैं। उनके अधिकतर उत्पाद घर से ही बिक जाते हैं। वे औषधीय खेती को लेकर किए जा रहे अपने काम को सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं। ऐसा करने पर उन्हें कई ऑर्डर मिलते हैं। वे अपने ड्राइ प्रोडक्टस को डाक के माध्यम से ग्राहक को भेजते हैं, जबकि लिक्विड प्रोडक्टस को कोरियर से भेजा जाता है।

जून 2022 को गोंडा के उपायुक्त डॉ. उज्जवल कुमार ने उनके फार्म का दौरा कर उनकी पीठ थपथपाई। उनके दौरे के दौरान हजारों किसान उनके फार्म में पहुंचे और यकायक वे सुर्खियों में आ गए। अब वे स्टूडेंट्स और किसानों को अपने फार्म की विजिट करवाते हैं और औषधीय खेती से संबन्धित महत्वपूर्ण जानकारी उनके साथ शेयर करते हैं। विभिन्न मंचों पर वे औषधीय कृषिकरण की संभावनाओं और चुनौतियों को लेकर संवाद करते हैं। उनके इस कृषि मॉडल से प्रभावित होकर कर कई किसान औषधीय पौधों की खेती कर रहे हैं।

आज दैनिक जागरण समाचार पत्र में अपनी बागवानी की डीएम गोंडा द्वारा विजिट की खबर छपी है।

औषधीय खेती बन गई कमाई का जरिय

जंगली सब्जियां होती हैं हैल्थ के लिए वरदान प्रोफेसर डॉ. तारा सोशल मीडिया पर बांट रहीं ज्ञान

आरसीएफसी नेटवर्क/हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश के पीजी कॉलेज मंडी में वनस्पति विज्ञान में सहायक प्रोफेसर डॉ. तारा देवी सेन ठाकुर सोशल मीडिया के माध्यम से जंगली खाद्य पौधों के उपभोग के लिए देश-विदेश के लोगों को प्रेरित कर रहीं हैं। वे स्कूली स्टूडेंट्स और दूरदराज क्षेत्रों की महिलाओं को इसके उपभोग के लिए सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर रहीं है। वे जंगली खाद्य पौधों, उनके औषधीय गुणों और उनसे बनने वाले विभिन्न व्यंजनों को लेकर आलेख लिखती हैं।

उनकी वेबसाइट https://himalayanwildfood-plants.com/ पर खाए जाने वाले विभिन्न जंगली खाद्य पौधों की गहन जानकारी उपलब्ध कारवाई गई है। उन्होंने स्वर्गीय डॉ. चिरणजीत परमार के साथ आईआईटी मंडी द्वारा प्रकाशित 'पश्चिमी हिमालय के कुछ जंगली खाद्य पौधे' पुस्तक का सहलेखन किया है। वे जंगली खाद्य पौधों के साथ नृवंशविज्ञान और जैव विविधता संरक्षण के प्रति समर्पित हैं।

जंगली खाद्य पौधों से बनने वाले पारंपरिक व्यंजनों को किया पुनर्जीवित

डॉ. तारा सेन मंडी जिले के 5 ब्लॉकों में जैव विविधता रजिस्टर तैयार करने में सक्रिय रही हैं। उन्होंने जंगली खाद्य पौधों से बनने वाले पारंपरिक व्यंजनों को पुनर्जीवित किया है। जंगली खाद्य पौधों से स्थानीय और पारंपरिक रूप से संसाधित खाद्य

पदार्थों की ऑनलाइन मार्केटिंग की राह आसान कर डॉ. तारा सेन ने कई सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को जंगली खाद्य पौधों से पारंपरिक व्यंजन बनाकर आय उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित किया है।

डॉ. तारा सेन प्रदेश सरकार के पर्यावरण और विज्ञान विभाग द्वारा आवंटित और वित्तपोषित मंडी जिला की छह तहसीलों कोटली, मंडी सदर, सुंदरनगर, पधर, जोगिंदरनगर, थुनाग और चच्योट के जंगली खाद्य पौधों की पारंपरिक व नवीनतम प्रसंस्करण तकनीकों के विश्लेषण तथा औषधीय पोषण व मूल्य संवर्धन शोध परियोजना की मुख्य अन्वेषक रही हैं। वे आयुष मंत्रालय के राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड की 'अश्वगंधा-हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में स्वास्थ्य और प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने के लिए खेती और इष्टतम उपयोग के लिए जागरूकता' परियोजना की मुख्य अन्वेषक हैं। उन्होंने मध्य हिमालयी जलग्रहण परियोजना में एक सुविधाकर्ता के रूप में भी कार्य किया है।

राष्ट्रीय - अंतरराष्ट्रीय पत्रिकाओं में 18 शोध पत्र प्रकाशित

डॉ. तारा सेन ने प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला से बीएससी, जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर से वनस्पति विज्ञान में एमएससी, सिक्किम मणिपाल विश्वविद्यालय से पर्यावरण विज्ञान में एमएससी और कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल से पीएचडी की है। डॉ. तारा सेन के विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में जंगली खाद्य पौधों से संबन्धित विभिन्न विषयों जैसे पौधों की विविधता, स्थानिकता, वितरण, वर्गीकरण, पारंपरिक व स्वदेशी उपयोग, औषधीय क्षमता, पर्यटन विकास में जंगली खाद्य पौधों की भूमिका, प्रतिरक्षा बढ़ाने में जंगली खाद्य पौधों की भूमिका, जंगली खाद्य पौधों का संरक्षण, प्रबंधन और आर्थिक क्षमता पर 18 शोध पत्र प्रकाशित हो चुके हैं। डॉ. तारा पर्यावरण, विकास और स्थिरता पर अंतर्राष्ट्रीय जर्नल के संपादकीय बोर्ड की सदस्य और हिम विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन की भी सदस्य हैं।

हिमाचल की 13वीं प्रभावशाली महिला

डॉ. तारा सेन को तत्कालीन ग्रामीण विकास और पंचायतीराज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने सम्मानित किया है। जंगली खाद्य पौधों के उपयोग के लिए जनता को जागरूक करने के लिए उन्हें कोरोना योद्धा के रूप में सम्मान मिला है। जंगली खाद्य पौधों से संबंधित टीके के संरक्षण के लिए उन्हें इंटैक ने पुरस्कृत किया है। उन्हें सामुदायिक सेवाओं के लिए आर्ट ऑफ लिविंग महिला क्लब मंडी ने सम्मानित किया है। प्रदेश बाल कल्याण विभाग के 2021 की सबसे शक्तिशाली महिलाओं के वार्षिक कैलेंडर में उन्हें 13वें नंबर पर रखा गया है।

उन्हें राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने पुरस्कृत किया है। उन्हें औषधीय पौधों के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए औषध पादप बोर्ड के क्षेत्रीय सुविधा केंद्र जोगिन्द्रनगर ने सम्मान दिया है। द सोसाइटी ऑफ ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर नई दिल्ली ने उन्हें रियल सुपर वुमन अवार्ड 2021 प्रदान किया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने उन्हें राज्य नेतृत्व पुरस्कार 2021-22 में दूसरा पुरस्कार प्रदान किया है। युवा जागृति एवं जन कल्याण मिशन ट्रस्ट भिवानी ने उन्हें राष्ट्रीय सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षक पुरस्कार 2023 और दिल्ली विश्वविद्यालय के शिवाजी कॉलेज ने उन्हें जीजाबाई अचीवर्स अवार्ड 2024-25 से सम्मानित किया है।

खेती करने से पहले ही शुरू कर दीजिये लीगल प्रिक्योरमेंट सार्टिफिकेट की प्रोसेस

आरसीएफसी नेटवर्क/हिमाचल प्रदेश

साइटिस (वन्य जीव और वनस्पति की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन) सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जंगली जानवरों और पौधों के नमूनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से प्रजातियों के अस्तित्व को कोई खतरा न हो। साइटिस के शेड्यूल-1 और शेड्यूल-2 के अंदर जो भी औषधीय पौधे वर्णित किए गए हैं, उनको अंतरराष्ट्रीय व्यापार में ले जाने के लिए साइटिस का सर्टिफिकेट जरूरी है।

साइटिस सर्टिफिकेट बनवाने के लिए लीगल प्रिक्योरमेंट सर्टिफिकेट लगता है, जिस के लिए 'एलपीसी' शब्द प्रचलन में है। एक एलपीसी तो वहां बनता है, जहां पर औषधीय कृषिकरण हुआ है। इसके लिए औषधीय खेती करने वाले किसान को वहां के राजस्व विभाग और वन विभाग को खेती से पहले सूचना देनी होती है।

यूं तो एलपीसी बहुत बड़ा मसला भी नहीं है। साल में दो बार राजस्व विभाग खेतों की गिरदावरी करता है। हर खेत में विजिट करना और खेतों में जो भी उगाया जा रहा है, उसकी एंट्री करना विभाग की जिम्मेदारी होती है। चूंकि अधिकतर किसान अपने खेतों में परंपरागत फसलें उगाते हैं, इसलिए औषधीय कृषिकरण को अलग से दर्ज करने की परंपरा नहीं रही है।

ऐसे में औषधीय कृषिकरण करने वाले किसान को खुद आगे आकर गिरदावरी करने आए पटवारी को मौके पर अपने खेत दिखा कर उनमें की गई औषधीय खेती का विवरण राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाना चाहिए। अगर गिरदावरी के वक्त ऐसा करवाना संभव नहीं हो पाए तो पटवारखाने जाकर इस बारे में पटवारी को सूचित करना चाहिए।

आयुष हर्ब्स के चेयरमैन जितेंद्र सोढ़ी कहते हैं कि उनकी कंपनी हिमाचल प्रदेश में 29 ऐसी दिव्य औषधियों के कृषिकरण पर काम कर रही है, जिनका वजूद खतरे में है। वे कहते हैं कि औषधीय उत्पाद को बेचने के लिए हार्वेस्टिंग के बाद की प्रक्रिया बेहद जटिल है। ऐसे में कोई भी किसान औषधीय कृषिकरण को आगे नहीं आयेगा।

औषधीय कृषिकरण को बढ़ावा देने के लिए इस प्रोसेस को बहुत सरल बनाने की जरूरत है। जितेंद्र सोढ़ी सुझाव देते हैं कि जिस भी एरिया में औषधीय खेती की जा रही है, औषध पादप बोर्ड को उसका प्रमाणीकरण करना चाहिए। अगर किसान के पास औषध पादप बोर्ड का सर्टिफिकेट होगा तो उसे एलपीसी लेने में किसान को आसानी हो जाएगी। जितेंद्र सोढ़ी कहते हैं कि राजस्व विभाग और वन विभाग के अधिकतर अधिकारियों-कर्मचारियों की भी एलपीसी बनाने को लेकर ट्रेनिंग करवाई जानी चाहिए।

बड़े स्तर पर औषधीय खेती करवा रही आयुष हर्ब्स

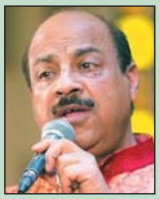

पिछले सो तीन दशक से औषधीय कृषिकरण और प्रोसेसिंग में अपनी अंतरराष्ट्रीय पहचान बनाने वाली कांगड़ा जिला के नगरोटा बगवां इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित आयुष हर्ब्स कंपनी के चेयरमैन जितेंद्र सोढ़ी ने कुछ साल पहले सर्पगंधा को अंतरराष्ट्रीय बाजार में अच्छा मूल्य दिलाने, उसके संरक्षण और संवर्धन के दृष्टिकोण से कार्य शुरू किया। उन्होंने पंजाब के किसानों के बड़े स्तर पर साथ सर्पगंधा की खेती की।

उन्होंने औषध पादप बोर्ड के सहयोग से ऊना में तैयार नर्सरी से अश्वगंधा का क्वालिटी प्लांटिंग मैटेरियल लेकर किसानों से दो एकड़ में तीन लाख पौधे लगवाए।

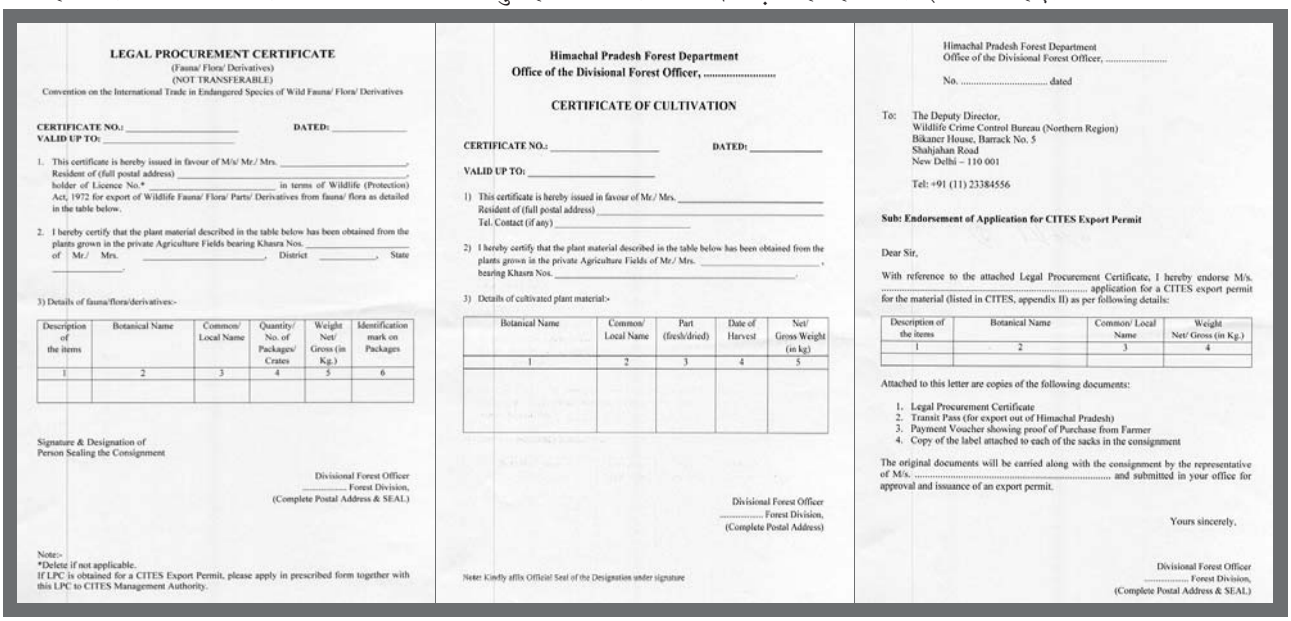

LEGAL PROCUREMENT CERTIFICATE
(Fauna/ Flora/ Derivatives)
(NOT TRANSFERABLE)
Convention on the International Trade in Endangered Species of Wild Fauna/ Flora/ Derivatives

CERTIFICATE NO.: _____ DATED: _____
VALID UP TO: _____

1. This certificate is hereby issued in favour of M/s/ Mr./ Mrs. _____, Resident of (full postal address) _____ holder of Licence No.* _____ in terms of Wildlife (Protection) Act, 1972 for export of Wildlife Fauna/ Flora/ Parts/ Derivatives from fauna/ flora as detailed in the table below.
2. I hereby certify that the plant material described in the table below has been obtained from the plants grown in the private Agriculture Fields bearing Khasra Nos. _____ of Mr./ Mrs. _____, District _____, State _____.
3) Details of fauna/flora/derivatives:-

Description of the items	Botanical Name	Common/ Local Name	Quantity/ No. of Packages/ Crates	Weight Net/ Gross (in Kg.)	Identification mark on Packages
1	2	3	4	5	6

Signature & Designation of Person Sealing the Consignment

Divisional Forest Officer
..... Forest Division,
(Complete Postal Address & SEAL)

Note:-
*Delete if not applicable.
If LPC is obtained for a CITES Export Permit, please apply in prescribed form together with this LPC to CITES Management Authority.

Himachal Pradesh Forest Department
Office of the Divisional Forest Officer, ...

CERTIFICATE OF CULTIVATION

CERTIFICATE NO.: _____ DATED: _____
VALID UP TO: _____

1) This certificate is hereby issued in favour of Mr./ Mrs. _____ Resident of (full postal address) _____ Tel. Contact (if any) _____
2) I hereby certify that the plant material described in the table below has been obtained from the plants grown in the private Agriculture Fields of Mr./ Mrs. _____, bearing Khasra Nos. _____.
3) Details of cultivated plant material:-

Botanical Name	Common/ Local Name	Part (fresh/dried)	Date of Harvest	Net/ Gross Weight (in kg)
1	2	3	4	5

Divisional Forest Officer
..... Forest Division,
(Complete Postal Address)

Note: Kindly affix Official Seal of the Designation under signature

Himachal Pradesh Forest Department
Office of the Divisional Forest Officer, ...

No. ..... dated

To: The Deputy Director,
Wildlife Crime Control Bureau (Northern Region)
Bikaner House, Barrack No. 5
Shahjahan Road
New Delhi – 110 001

Tel: +91 (11) 23384556

Sub: Endorsement of Application for CITES Export Permit

Dear Sir,

With reference to the attached Legal Procurement Certificate, I hereby endorse M/s. ..... application for a CITES export permit for the material (listed in CITES, appendix II) as per following details:

Description of the items	Botanical Name	Common/ Local Name	Weight Net/ Gross (in Kg.)
1	2	3	4

Attached to this letter are copies of the following documents:

1. Legal Procurement Certificate
2. Transit Pass (for export out of Himachal Pradesh)
3. Payment Voucher showing proof of Purchase from Farmer
4. Copy of the label attached to each of the sacks in the consignment

The original documents will be carried along with the consignment by the representative of M/s. ..... and submitted in your office for approval and issuance of an export permit.

Yours sincerely,

Divisional Forest Officer
..... Forest Division,
(Complete Postal Address & SEAL)

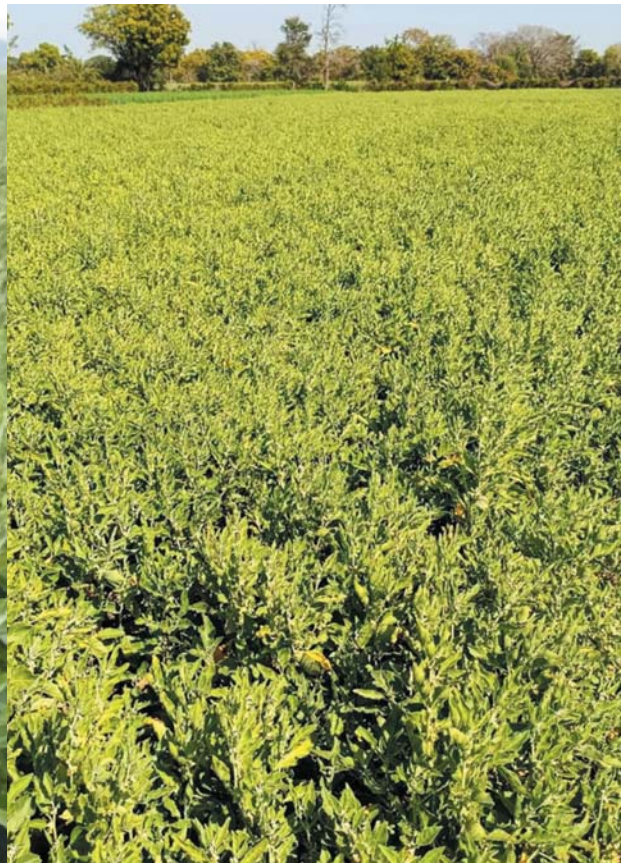

वन व राजस्व विभाग को एलपीसी और साइटिस के बारे में जानकारी ही नहीं है। जानकारी के अभाव के चलते ही वे किसान को एलपीसी देने को इंकार करते हैं। जितेंद्र सोढ़ी का कहना है कि औषधीय उत्पादों के निर्यात से जुड़े एलपीसी और साइटिस सार्टिफिकेट्स के बारे में दोनों विभागों के अफसरों की एजुकेशन और ट्रेनिंग होनी चाहिए। किसान को अगर ऐसे सर्टिफिकेट आसानी से मिलेंगे, तभी मृतप्राय औषधीय पौधों की खेती की राह आसान होगी।

एलपीसी के बारे में अंजान अफसर

एलपीसी लेने के लिए जितेंद्र सोढ़ी की सलाह पर किसानों ने राजस्व विभाग और वन विभाग को समय-समय पर सूचित किया और राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज भी करवाया। जब फसल तैयार हुई, तो किसान जब एलपीसी के लिए वन विभाग के पास गए। जवाब मिला कि यह काम विभाग के प्रिव्यू में नहीं है। राजस्व विभाग से भी कुछ ऐसा ही जबाव मिला। दोनों विभागों के शीर्ष अधिकारियों को एलपीसी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी।

जितेंद्र सोढ़ी उसके बाद इस मुद्दे को लेकर राष्ट्रीय औषध पादप बोर्ड के क्षेत्रीय सुविधा केंद्र उत्तर भारत, जोगिंदरनगर के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर अरुण चंदन के पास पहुंचे। राष्ट्रीय औषध पादप बोर्ड के हस्तक्षेप के बाद की एलपीसी बना, जिससे साइटिस के सर्टिफिकेट का रास्ता साफ हुआ।

प्रोसेसिंग के लिए अलग से एलपीसी

साइटिस के सर्टिफिकेट के लिए प्रोसेसिंग फैसिलिटी देने वाली यूनिट के पास भी लीगल प्रिक्योरमेंट सर्टिफिकेट होना जरूरी है। जितेंद्र सोढ़ी बताते हैं कि एलपीसी के साथ जब उन्होंने साइटिस के सर्टिफिकेट के लिए आप्लाई किया, तो साइटिस की तरफ से जवाब आया कि कल्टिवेशन का एलपीसी ठीक है। अश्वगंधा की खेती पंजाब में हुई है और उसकी प्रोसेसिंग हिमाचल प्रदेश में हो रही है। इसलिए प्रोसेसिंग फैसिलिटी देने वाली यूनिट का भी एलपीसी चाहिए।

जितेंद्र सोढी के मुताबिक इस बार भी एलपीसी के लिए फिर से संबन्धित विभागों की तरफ से पुरानी ही कहानी दोहराई गई। वे कहते हैं कि डेढ़ साल की जद्दोजहद के बाद भी औषधीय पौधों के निर्यात के लिए बनने वाले लाईसेंस के लिए जरूरी प्रोसेसिंग यूनिट का सरकारी एलपीसी नहीं बन पाया है। इस बार भी औषध पादप बोर्ड के क्षेत्रीय सुविधा केंद्र के हस्तक्षेप के बाद ही प्रोसेसिंग के लिए भी एलपीसी जारी करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। जितेंद्र सोढ़ी इसे सरल बनाने की वकालत करते हैं।

प्रिसीजन एग्रीकल्चर-एस्टेब्लिश होगी रियल टाइम ट्रेसेबिलिटी

औषध पादप बोर्ड के क्षेत्रीय सुविधा केंद्र के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर अरुण चंदन कहते हैं कि

वर्तमान युग प्रिसीजन एग्रीकल्चर का है। प्रिसिजन एग्रीकल्चर एक आधुनिक कृषि तकनीक है जो विभिन्न उपकरणों और डेटा विश्लेषण पर आधारित है। औषधीय कृषिकरण में भी इस तकनीक का प्रयोग समय की मांग है। इससे हम औषधीय कृषिकरण की रियल टाइम ट्रेसेबिलिटी एस्टेब्लिश कर सकते हैं। वे कहते हैं कि उन्हें यकीन हैं कि रियल टाइम ट्रेसेबिलिटी को लेकर साइटीज भी सहमत होगी।

डॉक्टर अरुण चंदन का कहना है कि भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के तहत औषध पादप बोर्ड पिछले पच्चीस वर्षों से एक सौ चालीस के करीब औषधीय पौधों के संरक्षण और संवर्धन में जुटा है। नेशनल आयुष मिशन के अंतर्गत औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देने के लिए करीब चार सौ करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। 2017 में औषधीय पौधों की सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए क्षेत्रीय सुविधा केंद्र खुले हैं। क्षेत्रीय सुविधा केंद्र उत्तर भारत ने औषधीय कृषिकरण में प्रिसीजन एग्रीकल्चर के प्रयोग के लिए औषध पादप बोर्ड को सुझाव भेजा है।

जड़ी-बूटियों की खेती के लिए देश भर में तैयार किए जा रहे हैं भारतीय सेना के जवान

आरसीएफसी नेटवर्क/दिल्ली

भारतीय सेना के फौजियों के साथ यह विडम्बना है कि रिटायरमेंट के बाद सिविल सोसायटी में उनकी कोई पूछ नहीं होती। देश के ग्रामीण अंचलों से संबंध रखने वाले उम्रभर अनुशासन में रहे ऐसे फौजियों की सैन्य ट्रेनिंग बेकार चली जाती है और उन्हें सिक्युरिटी गार्ड जैसे पद मिलते हैं। उम्र के जिस दौर में सैनिक रिटायर्ड होता है, उसके बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे होते हैं, ऐसे में उस पर पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, लेकिन मासिक आय कम हो जाती है।

कर्नल राजेश कुमार ने इस समस्या के समाधान के लिए एक अनूठी राह निकाली है। वे जहां भी तैनात होते हैं, जल्द रिटायर्ड होने वाले फौजियों को औषधीय कृषिकरण के लिए प्रेरित करते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं और औषधीय कृषिकरण के विशेषज्ञों से उनकी ट्रेनिंग करवाते हैं। वे अब तक कई सैनिकों को जड़ी-बूटियों की खेती के लिए प्रशिक्षित कर चुके हैं और 100 से अधिक सैनिक सेवानिवृति के बाद जड़ी-बूटियों की खेती और उसकी प्रोसेसिंग कर हर्बल उत्पाद बना रहे हैं।

इस तरह आया औषधीय कृषिकरण का आइडिया

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से संबंध रखने वाले दिल्ली में पले-बढ़े हुए कर्नल राजेश कुमार जबलपुर से पशु चिकित्सा की डिग्री ली है। पढ़ाई के दौरान उन्हें घुड़सवारी का शौक रहा। कुछ साल उन्होंने राजस्थान से पशुपालन विभाग में बतौर पशु चिकित्सक सेवाएं प्रदान की। उन्होंने देहरादून स्थित वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ काम करने के अलावा दिल्ली में एनिमल क्लीनिक भी संचालित किया। पिछले पैंतीस सालों से भारतीय सेना में सेवाएं दे रहे कर्नल राजेश कुमार कोविड काल में कांगड़ा के चड़ी स्थित वेटनरी यूनिट में तैनात रहे। इसी दौरान वे औषध पादप बोर्ड के क्षेत्रीय सुविधा केंद्र के क्षेत्रीय निदेशक डॉ. अरूण चंदन के संपर्क में आए। पहले उन्होंने खुद औषधीय कृषिकरण से संबंधित प्रशिक्षण लिया और फिर अपनी यूनिट में जल्द रिटायर्ड होने वाले फौजियों के लिए केंद्र के विशेषज्ञों की सेवाएं लीं।

क्षेत्रीय सुविधा केंद्र का साथ, कर्नल की धर्मवीर कंबोज से मुलाकात

क्षेत्रीय सुविधा केंद्र उत्तर भारत, जोगिन्द्रनगर के क्षेत्रीय निदेशक डॉ. अरुण चंदन ने कर्नल राजेश कुमार को हरियाणा के यमुनानगर के प्रगतिशील किसान एवं मल्टी प्रोसेसिंग मशीन का निर्माण करने धर्मवीर कंबोज से मुलाकात संभव करवाई। कर्नल राजेश कुमार ने धर्मवीर कंबोज से जड़ी-बूटियों की प्रोसेसिंग कर उत्पाद बनाने का हुनर सीखा है। वे कहते हैं कि क्षेत्रीय सुविधा केंद्र के क्षेत्रीय निदेशक डॉ. अरुण चंदन उनके लिए गुरु समान हैं, जिन्होंने उन्हें जड़ी-बूटियों के बारे में गहरे अध्ययन के लिए प्रेरित किया है।

सेना से रिटायरमेंट के बाद कर्नल राजेश कुमार जड़ी-बूटियों और ओर्गेनिक खेती करने का पूरा मन बना चुके हैं। वे हिमाचल प्रदेश में बसकर औषधीय कृषिकरण के मोर्चे पर डटने वाले हैं और बतौर पशु चिकित्सक निरीह जानवरों की सेवा के लिए तत्पर हैं। इसके लिए उन्होंने हिमाचल प्रदेश सरकार से परमिशन मिलने के बाद कांगड़ा जिला में जमीन खरीदी है, जहां वे जड़ी- बूटियों की खेती कर उन्हें प्रोसेस कर हर्बल उत्पाद तैयार करने की योजना पर काम करने लगे है।

सिद्धा में सिद्ध हो रहे कर्नल राजेश

पशु चिकित्सक कर्नल राजेश ने आयुर्वेद में अपनी समझ विकसित करने के लिए गहन अध्ययन किया है। इसी अध्ययन के दौरान उन्हें हिमालय में पाई जाने वाली उच्च मूल्य वाली दिव्य जड़ी बूटियों के बारे में जानकारी मिली।

वे वर्तमान में चेन्नई में तैनात हैं। कर्नल राजेश तामिलनाडु, केरल और आंध्रप्रदेश सहित कई राज्यों में प्रभावशाली भारतीय चिकित्सा पद्दति 'सिद्धा' को सीख रहे हैं। आयुर्वेद की तरह ही जड़ी-बूटियों से बनीं औषधियों से उपचार करने वाली इस परंपरागत चिकित्सा पद्धति की खासी साख है।

कर्नल राजेश चेन्नई में भी औषधीय कृषिकरण और प्राकृतिक खेती के लिए मिशन चलाए हुए हैं। वे औषधीय पौधों और प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों से जुड़े हुए हैं। यहां भी वे फौजियों को रिटारमेंट के बाद औषधीय खेती करने के लिए तैयार कर रहे हैं। कर्नल राजेश कुमार का कहना है कि रिटायरमेंट से पहले जड़ी-बूटियों की खेती के लिए फौजियों का कौशल निर्माण औषधीय कृषिकरण में क्रांति ला सकता है, क्योंकि अधिकतर सैनिक ग्रामीण भारत के कृषक पृष्ठभूमि वाले परिवारों से आते हैं।

जड़ी-बूटी बाज़ार
औषधीय खेती के लिए उत्तर प्रदेश में एनएमपीबी को मिला बीएचयू का साथ
क्षेत्रीय एवं सुगमता केंद्र उत्तर भारत की पहल
औषध कृषिकरण
सहकारिता में औषधीय कृषिकरण का अनूठा मॉडल, हमीरपुर में 30 सहकारी सभाएं मिल कर रही हैं खेती
सिंचाई के लिए नहीं पानी, पांच सौ किसानों ने एलोविरा उगाकर लिख दी नई कहानी
हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिला के बमसन ब्लॉक में देश की अनूठी पहल
उत्पादकों, किसानों, शोधकर्ताओं और व्यापारियों के लिए स्टॉप शॉप
क्षेत्रीय एवं सुगमता केंद्र उत्तर भारत, जोगिंद्रनगर
सफल प्रयोग
जन जातीय पांगी घाटी के कृषि उत्पादों के लिए 'सेवा' की पहल से चंबा में खुला 'पांगी हिल्स रूरल मार्ट'
विदेशों तक पहुंचा दिए जंगली उत्पाद, महिलाओं ने रखी कारोबार की बुनियाद
कुटकी से चमका चमोली का घेस गांव, बनेगा देश का 'आयुष ग्राम'
प्रोसेसिंग
धर्मवीर ने जुगाड़ से ऐसी मशीनें बनाईं, जड़ी- बूटियों की खेती से बढ़ी कमाई
अपने खेतों में उगाएं बेशकीमती सर्पगंधा, 18 माह में ही चमक उठेगा आपका धंधा
ई-कॉमर्स
जीवनीय नेचुरल
LUCKNOW'S FIRST ORGANIC SUPERSTORE
हल्दी की खेती ने कर्नल को फल दिया जल्दी
ई-चरक
औषधीय फसल बेचने की राह हुई अब आसान, किसानों को ऑनलाइन मिल जाएगा फसल का खरीददार
ई-चरक : जड़ी-बूटियों की खरीदने-बेचने का ऑनलाइन प्लेटफार्म
जड़ी-बूटी खरीदने-बेचने के लिए संपर्क
पते की बात
'कांगड़ा चाय' में पालमपुर का जायका